



लोगों के जीवन के साथ जुआ न खेलें :
स्वाति मालीवाल

पृष्ठ-2

दिव्य भारत



बदले की राजनीति करना बंद करे मान
सरकार : चुग

पृष्ठ-3

लोकसभा में पारित हुआ वक्फ विधेयक

विधेयक के पक्ष में 288 और खिलाफ में 232 वोट पड़े

रमाकान्त पाण्डेय

नई दिल्ली। लोकसभा में आधी रात को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े। इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। मोदी सरकार के लिए यह बड़ी परीक्षा थी। एनडीए ने इस बिल के पक्ष में पूरी तरह से एकजुटता दिखाई। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि यह बिल मुस्लिम, इस्लाम विरोधी नहीं है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। विपक्षी सांसदों के सभी संशोधन खरिज कर दिए गए।

चर्चा का जवाब देते हुए किरन रिजिजू ने कहा कि मैं सभी नेताओं को बिल के बारे में अपने विचार रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ नेता कह रहे हैं कि बिल असंवैधानिक है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे कैसे कह सकते हैं कि बिल असंवैधानिक है। अगर यह असंवैधानिक था, तो कोर्ट ने इसे रद्द क्यों नहीं किया? असंवैधानिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए... बिल



संविधान के खिलाफ नहीं है, जैसा कि विपक्ष ने दावा किया है। हमें 'संवैधानिक' और 'असंवैधानिक' शब्दों का इस्तेमाल इतने हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवैसी ने विभिन्न मुद्दे उठाते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों के लिए वक्फ में मुसलमानों के बच्चों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के लिए पहले से ही प्रावधान है। इस पर कोई दूसरा कानून बनाने की जरूरत नहीं है। सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शाह ने स्पष्ट किया कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि (विपक्ष द्वारा) मुस्लिम भाइयों को इस बहाने

डराया जा रहा है। शाह ने कहा, यह पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में (वक्फ की जमीन के लिए) जो मिलीभगत चल रही है वह अब नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने कहा, वे कहते हैं कि इसका (वक्फ की संपत्ति) हिसाब-किताब न करो, लेकिन इसका पैसा देश के गरीबों के लिए है न कि धन्या सेटों के चोरी करने के लिए है। शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में है। उन्होंने द्रमुक सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि विधेयक का विरोध कर वे दक्षिण (भारत) के सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं।

किसी से नहीं चाहिए
धर्मनिरपेक्षता का
सर्टिफिकेट : ललन सिंह

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में शामिल जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने लोकसभा में बुधवार को पेश वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। विधेयक पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए पार्टी नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी के 20 साल के बिहार में शासन के दौरान मुसलमानों के हित में सबसे ज्यादा काम हुआ है। उन्होंने किसी से धर्मनिरपेक्षता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जद(यू) नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि वक्फ के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह मुस्लिम विरोधी है। वक्फ मुस्लिम संस्था नहीं है। वक्फ केवल एक ट्रस्ट है। वक्फ बोर्ड केवल एक प्रशासनिक और विनियामक संस्था है। ट्रस्ट को चाहिए कि वे महिला और पसमंदा मुसलमानों सहित सभी मुसलमानों के साथ न्याय करें। विधेयक का विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं, एक वे जिन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है और दूसरा वे जिनका वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है। मोदी सरकार वक्फ को लेकर पारदर्शिता और संपत्ति से होने वाली आमदनी बढ़ाना चाहती है। जातीय जनगणना पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने पसमंदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया और कहा कि पसमंदा मुसलमानों की गणना भी होनी चाहिए।

वक्फ को संविधान से ऊपर शक्ति देने का पाप कांग्रेस ने किया था : शाह

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ विधेयक में 2013 में संशोधन कर वक्फ को संविधान से भी ऊपर असीमित शक्ति देने का पाप किया था। इसके कारण 2013 से 2025 तक वक्फ की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। साथ ही उस समय हड़पी गई जमीन के खिलाफ पीड़ित का न्यायालय के पास जाने का अधिकार भी छीन लिया गया था।

गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद से 2025 के बीच में वक्फ संपत्ति में 21 लाख एकड़ जमीन की वृद्धि हुई है जबकि यह 2013 तक केवल 18 लाख एकड़ थी।

उन्होंने कहा, सरकार या संगठन का कोई निर्णय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति की जमीन ली गई है, वह कहाँ जाएगा? कांग्रेस ने वोट-बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया और हम इसे अस्वीकार कर रहे हैं। शिकायतों वाला कोई भी व्यक्ति अदालत से संपर्क कर सकता है।

शाह ने कहा कि विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति का बेहतर प्रबंधन है ताकि इससे होने वाली आमदनी को बढ़ाया जा सके। आमदनी का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए होगा लेकिन वर्तमान में पैसा चोरी हो रहा है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद इस चोरी को रोकेंगे।

इस संबंध में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2001-12 के बीच दो लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थाओं को सौ साल की लीज पर हस्तांतरित कर दी गई। बंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में दखल देना पड़ा और 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। ये पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, ये धन्यासेटों की चोरी के लिए नहीं है।

गृह मंत्री ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान का उल्लेख किया और कहा कि तब उन्होंने कहा था कि वह वक्फ पर एक सख्त कानून



चाहते थे और उन लोगों को जेल में डालना चाहते थे, जो चोरी कर रहे थे। नरेन्द्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव की इच्छाओं को पूरा किया है।

विपक्ष पर भ्रम फैलाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पिछड़े वर्गों या मुसलमानों के बारे में चिंतित नहीं हैं। वर्षों से उन्होंने जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया। इन समुदायों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक सोची समझी रणनीति के माध्यम से परिवार-केंद्रित राजनीति को बढ़ावा दिया। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जातिवाद, तुष्टीकरण और भाई-भतीजावाद को मिटा दिया है और बजाय विकास की राजनीति की स्थापना की है।

शाह ने इस दौरान स्पष्ट किया कि संसद सर्वोपरि है और उसमें पारित कानून को सभी को मानना होगा। एक सदस्य ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, कोई भी कैसे कह सकता है, 'हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे'? यह भारत सरकार का एक कानून है, और यह सभी पर लागू होता है। यह सभी के लिए बाध्यकारी है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ की अवधारणा इसके उपयोग पर आधारित होनी चाहिए और उपयोग की जा रही भूमि का अभी तक पंजीकरण हो जाना चाहिए था। लेकिन मुगल काल की प्रथाओं के आधार पर आज किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता।

आम मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के साथ : दानिश आजाद

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने बुधवार को पत्रकारों को कहा कि मुसलमान के विकास के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहद जरूरी कदम है। इस एक्ट के माध्यम से मुस्लिम समाज की वक्फ की जो संपत्तियाँ उसको ऑर्गेनाइजर और रेगुलराइज करने में बहुत मदद मिलेगी।

आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ हैं। कुछ खास राजनीतिक दल और कुछ खास लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों पर जिन्होंने अवैध कब्जे बनाकर रखे हैं, वहीं इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आम मुसलमान खासतौर पर पिछड़ा पसमंदा मुसलमान पूरी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के साथ हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने

कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होगी। जिससे बोर्ड के आय में वृद्धि होगी, इसका सीधा लाभ मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए हो सकेगा। इसके अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिस वक्त की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं, वह कब्जे हटेंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में महिला समाज और पसमंदा समाज ही हिस्सेदारी से

मुस्लिम समाज को और बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए होना भी सुनिश्चित



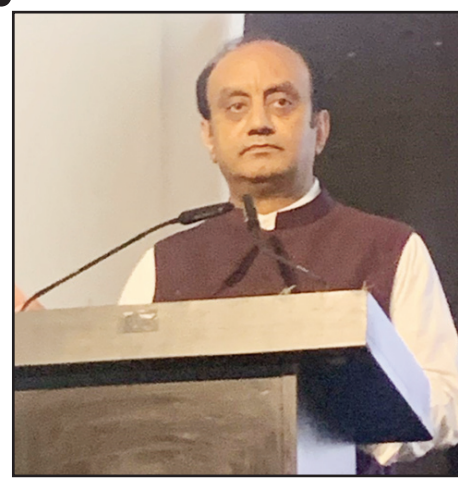
■ वक्फ कानून के पक्ष में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

होगा। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन कांग्रेस और तमाम वह दल जो अपने आप को मुसलमान का हितैषी बताते हैं। उन्होंने कभी भी हम मुसलमान के ठोस विकास के लिए काम नहीं किया। आज मुसलमान के ठोस विकास के लिए यदि मोदी सरकार काम कर रही है तो अगर यह मुस्लिम समाज को और बल मिलेगा।

विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान की हितैषी होती तो इस बिल का विरोध नहीं करती बल्कि इसका साथ देती।

बौद्धिक दासता से मुक्त होकर विकसित भारत की यात्रा में सहभागी बनें : सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली, (हि.स.)। विख्यात वक्ता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि हमें बौद्धिक दासता से मुक्त होकर अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना चाहिए। विश्व की अनेक सत्ताओं ने षडयंत्र रचकर हमारे इतिहास को विकृति किया, लोगों के मन में बैठाने का प्रयास किया कि भारत में जो कुछ भी अच्छा हुआ, वह मुगलों या अंग्रेजों के द्वारा किया गया। हम मैकाल और मार्क्स के रचित इतिहास से बाहर निकल रहे हैं और हम पाते हैं कि वे लुटेरे ने केवल हमारी आर्थिक समृद्धि को लूटकर ले गए बल्कि हमें मानसिक रूप से भी गुलाम बना गए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे सारे झूठ का पदार्फाश हो रहा है और देशवासी सच को जान रहे हैं और अपनी प्राचीन ऐतिहासिक विरासत और ज्ञान-विज्ञान पर गर्व कर रहे हैं।



डॉ. सुधांशु त्रिवेदी बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा आयोजित प्रो. देवेन्द्र स्वरूप स्मारक व्याख्यान को संबोधित रहे थे। समारोह की अध्यक्षता कला केन्द्र के अध्यक्ष पद्म भूषण रामबहादुर राय ने की। डॉ. त्रिवेदी ने अनेक संदर्भों का हवाला देते हुए सिद्ध

किया कि किस तरह आक्रमणकारियों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। दुर्भाग्य से उनसे प्रभावित हमारे ही कुछ लोगों ने भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और विरासत के साथ ही ज्ञान विज्ञान को भी कमतर आंकने के षडयंत्र रचे। इतिहास के नाम पर कोरा झूठ पढ़ाया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली का कुतुब मीनार ही है। एनसीईआरटी तक इसका प्रमाण नहीं दे पाई कि कुतुब मीनार किसने बनवाया। जबकि उसी मीनार के बगल में स्थित लौह स्तम्भ भारत की गौरवशाली विरासत है। उन्होंने कहा कि हमें समृद्ध भारत के गौरवशाली इतिहास और परम्पराओं को

जानना-समझना चाहिए, उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प जीवंत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के लालकिले की प्राचीर से किए गए आह्वान को अपना मंत्र बना लें। हमें गुलाम मानसिकता से मुक्ति, अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करना होगा और देश के लिए जो कर्तव्य है वह सामूहिकता में पूरे करने होंगे।

इस अवसर पर प्रो. देवेन्द्र स्वरूप की विद्वता और इतिहास दृष्टि की विशिष्टता बताते हुए रामबहादुर राय ने कहा कि हमारे शास्त्रों में छिपे इतिहास पर वे अपने जीवन के अंतिमकाल तक शोध करते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वास्तविक इतिहास लिखने और भारतीय ज्ञान परम्परा की गहराइयों को समझने के लिए वे बहुत अध्ययन करते थे। हमें उनके बचे हुए इस कार्य को पूरा करना है।

मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए कमर कसी

नई दिल्ली, (हि.स.)। लोकसभा में सरकार के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करने के बाद से ही मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद में विधेयक पेश करने से पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके अपने रुख को पूरी तरह से साफ कर दिया है।

बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके अलावा अदालती प्रक्रिया का भी सहारा लेने की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि अब यह लड़ाई अंतिम समय तक लड़ी जाएगी जब तक की वक्फ संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया जाएगा।



जमीअत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार की मंशा और इस बिल को पेश करने की प्रक्रिया सही नहीं है। जबरन इस बिल को पेश करके संख्या बल पर पास कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते

हैं और इस बिल के खिलाफ एक लंबे आंदोलन चलाने की तैयारी के लिए मुसलमान से कमर कसने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के समर्थन में जो लोग हैं वह सरकार के साथ हैं और हम उन्हें अच्छी तरह से पहचान रहे हैं।

जमाअत ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सआदतुल्लाह हुसैनी ने भी एक बयान में इस बिल को संसद में पेश करने और सरकार के जरिए पास करने की कोशिश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमान को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। लेकिन सरकार अपने अडिगल रुख को अपनाते हुए इसे पास करना चाहती है। उनका कहना है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और इसके लिए लंबे आंदोलन के लिए भी तैयार हैं।

दिव्य भारत एकेडमी

UPP, UPSI, SSC, RRB Group-D, RRB NTPC
UPSSSC PET, AGNIVEER, ARMY, CTET, UPTET, STET, BANK
प्रवेश परीक्षा (B.Ed., नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि)
प्रतियोगी परीक्षाओं की सम्पूर्ण तैयारी

मो: 7459096357, 7985608203

पता: बहारिया, कुण्डा-प्रतापगढ़



विश्व ऑटिज्म दिवस पर सफदरजंग अस्पताल में जागरूकता वॉक का आयोजन।

नकली सैन्य अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तरी जिले के गुलाबी बाग थाना पुलिस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान उत्तम नगर के प्रताप गार्डन निवासी सुमित सिंह के रूप में हुई है। उसे 2023 में भारतीय सेना से निलंबित किया गया था। इसके बाद उसने भारतीय सेना के फर्जी दस्तावेज बनाए, लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पहनी और पीड़ितों से ठगी करने के लिए बैंक का इस्तेमाल किया। वह भारतीय सेना में नौकरी लगवाने का झांसा देकर अब तक कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर चुका है। उसके कब्जे से भारतीय सेना (रक्षा मंत्रालय) के तीन नकली नियुक्ति पत्र बरामद किए गए।

उत्तरी जिले के डीसीपी राजा बाठिया ने मंगलवार को बताया कि महिला अधिवक्ता पी. कोहली ने गुलाबी बाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि बीते वर्ष 24 अगस्त को तीस हजार की कोर्ट से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति उससे मिला, जिसने अपना परिचय सुमित सिंह के रूप में दिया और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल होने का दावा किया।

उसने अपना आईडी भी कार्ड दिखाया और भारतीय सेना के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) में सीधी भर्ती अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उनका नंबर ले लिया। शिकायत के मुताबिक अगले दिन सुमित ने उनसे संपर्क किया और एएफटी में उसके लिए सरकारी एडवोकेट की नौकरी दिलाने का वादा किया और वाहट्सएप पर दस्तावेज लेकर उन्हें एएफटी दिल्ली के लिए जाइनिंग लेटर भेजा और एक सितंबर को जाइन करने को कहा। नौकरी लगवाने की बातचीत के दौरान उसने शादी के लिए प्रपोज भी किया। एक अगस्त को सुमित ने मेस खर्च के लिए उनसे करीब 64 हजार रुपये ट्रांसफर करने को कहा, जो उन्होंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपित ने उनके भाई मिलन कोहली को प्रिंसिपल कंट्रोलर आफ डिफेंस अकाउंट (पीसीडीए) में हेड क्लर्क के रूप में नौकरी दिलाने का वादा कर दस्तावेज मांगे, जो उन्होंने 15 अगस्त को भेज दिए और फिर भाई के किट और मेस खर्च के लिए 50 हजार रुपये और 54 हजार रुपये ट्रांसफर करने को कहा। उसने उसे यह भी बताया कि उसका मोबाइल

फोन ब्लास्ट हो गया है और वह अपने पीए शहनवाज का फोन इस्तेमाल कर रहा है। पीड़ित महिला ने उसे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 6 मोबाइल फोन और नया सिम खरीदकर दिया। वह यहीं नहीं रुका पीड़ित से बोला कि उसके भाई का वेटन बढ़ा दिया गया है और उससे 82 हजार रुपये उसके खाते में ट्रांसफर करने को कहा। इसके बाद आरोपित ने उसके पिता को टेंडर दिलाने का वादा करीब तीन लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए और पीड़ित के पिता से उनकी पालिसी के नवीनीकरण के नाम पर 2.40 लाख रुपये की ठगी भी की। चार अक्टूबर को सुमित ने प्राइवेट कूरियर से उसके भाई को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजा। इस दौरान जालसाज ने उस पर शादी करने का दबाव बनाते हुए पांच लाख रुपये की मांग की और उनके परिवार को नौकरी और शादी का वादा करके फरार हो गया। पीड़िता को शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी की मदद से टीम ने बिंदापुर के इलाके में आरोपित का पता लगाया और छापेमारी करते हुए उसे किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया।

विश्व ऑटिज्म दिवस पर सफदरजंग अस्पताल में जागरूकता वॉक का आयोजन

नई दिल्ली, (हि.स.)। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर बुधवार को सफदरजंग अस्पताल के भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग ने सुशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) से पीड़ित व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देने के लिए ऑटिज्म जागरूकता वॉक का आयोजन किया।

सफदरजंग अस्पताल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, देखभाल करने वाले, छात्रों और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों ने भाग लिया। यह वॉक सफदरजंग अस्पताल से शुरू हुई और अस्पताल परिसर के प्रमुख क्षेत्रों से होते हुए जिसमें ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए शीघ्र निदान, चिकित्सा और सामुदायिक सहायता के महत्व पर ध्यान आकर्षित किया गया।

इस अवसर पर सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप बंसल ने न्यूरोडाइवर्जेंट व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऑटिज्म कोई दिव्यांगता नहीं है। अग्रणी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में से एक के रूप में सफदरजंग जागरूकता फैलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को वह देखभाल मिले, जिसके वे हकदार हैं। वीएमएससी की प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना ने कहा, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के साथ बातचीत करने और उनका समर्थन करने के लिए ज्ञान और संवेदनशीलता से लैस होना चाहिए। सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं।

सफदरजंग अस्पताल के

पॉलीमार्थलजिया रूमेटिका के विभागाध्यक्ष (एचओडी) डॉ. अजय गुप्ता ने बहु-विषयक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऑटिज्म के लिए चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्रणालियों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। निरंतर जागरूकता और नीति वकालत के माध्यम से हमारा लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है, जहां ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति पनप सकें और पूर्ण जीवन जी सकें।

यह कार्यक्रम देखभाल करने वालों और आम जनता को ऑटिज्म के लक्षणों, प्रारंभिक निदान के महत्व और स्पेक्ट्रम पर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में चिकित्सा और सहायता प्रणालियों की भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए हितकारी साबित होगा एक राष्ट्र, एक चुनाव : सुनील बंसल

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म द्वारा स्वामी विवेकानंद स्मृति राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर बुधवार को डीयू के वाइस रीगल लॉज स्थित कन्वेंशन हॉल में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए हितकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि सुधार की प्रक्रिया निरंतर होती है और देश को बेहतर बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है और यह भारत के लोकतंत्र के लिए हितकारी साबित होगा। साथ ही इस चुनाव प्रक्रिया से देश को नेतृत्व के लिए नए चेहरे मिलेंगे। उन्होंने बार बार चुनाव कराने की प्रक्रिया को देश के विकास के लिए स्पीड ब्रेकर बताया। उन्होंने छात्रों को वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उनकी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच की प्रशंसा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव अगर एक साथ हों तो समय और संसाधन बचेंगे तथा एक राष्ट्र एक चुनाव 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने वाला बताया। कुलपति ने कहा कि 1947 में देश के स्वतंत्र होने से लेकर अब तक करीब 400 चुनाव हो चुके हैं। यानी प्रत्येक वर्ष 5 चुनाव भारत में होते हैं। क्या यह देश के लिए ठीक है? चुनाव के कारण विकास एवं शासन से ध्यान हटता है और ये प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में देशभर से आए 70 से अधिक प्रतिभागियों में आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के आदित्य अग्रहरि और महक मौर्या ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी मेधा का परिचय दिया।

किया और उनकी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच की प्रशंसा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव अगर एक साथ हों तो समय और संसाधन बचेंगे तथा एक राष्ट्र एक चुनाव 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने वाला बताया। कुलपति ने कहा कि 1947 में देश के स्वतंत्र होने से लेकर अब तक करीब 400 चुनाव हो चुके हैं। यानी प्रत्येक वर्ष 5 चुनाव भारत में होते हैं। क्या यह देश के लिए ठीक है? चुनाव के कारण विकास एवं शासन से ध्यान हटता है और ये प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में देशभर से आए 70 से अधिक प्रतिभागियों में आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के आदित्य अग्रहरि और महक मौर्या ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी मेधा का परिचय दिया।

आज का राशिफल

मेघ राशि-स्त्री वर्ग से हर्ष-उल्लास, किसी तनावपूर्ण स्थिति में सुधार अवश्य ही होगा।
वृष राशि-कार्यवृत्ति अनुकूल, चिन्ताएँ कम हों, स्त्री वर्ग से हर्ष-उल्लास अवश्य ही होगा।
मिथुन राशि-कार्यवृत्ति अनुकूल, चिन्ताएँ कम हों, पारिवारिक समस्या निपटेंगी, कार्य होगा।
कर्क राशि-व्यवसायिक क्षमता अनुकूल रहेंगी, दैनिक स्थिति में सुधार अवश्य ही होगा।
सिंह राशि-समय पर सोचे हुए कार्य बनेंगे, इष्ट मित्र सुखवर्धक होंगे, समय का ध्यान दें।
कन्या राशि-सामाजिक कार्य में मान-प्रतिष्ठा नवीन कार्य फलीभूत हो सकते हैं, कार्य बनें।
तुला राशि-चिन्ताएँ कम हों, समय अनुकूल नहीं, विशेष कार्य फलीभूत हों सफलता मिले।
वृश्चिक राशि-मनोवृत्ति एवं भावनाएँ उत्साहवर्धक हों, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा।
धनु राशि-दैनिक कार्यवृत्ति अनुकूल, मनोकामना पूर्ण होगी, शुभ समाचार अवश्य मिलेगा।
मकर राशि-व्यर्थ धन व्यय, विरोधी परेशान अवश्य ही करेंगे, समय का ध्यान रखें।
कुम्भ राशि-समाज में मान-प्रतिष्ठा, प्रभुत्व वृद्धि होगी, व्यवसाय में साधन प्राप्त करें।
मीन राशि-तनाव व क्लेश, अशांति से बचते हुए कार्य अवश्य ही बिगड़ जायेंगे, विवाद से बचें।

-अम्बुजा तिवारी

महिला सशक्तीकरण के लिए सेवाभारती करेगी 'रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड' का आयोजन

नई दिल्ली, (हि.स.)। सामाजिक संस्था सेवाभारती, दिल्ली द्वारा 13 अप्रैल को यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मैराथन रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किशोरी विकास और महिला सशक्तीकरण है।

इसमें सेवा बस्तियों की लड़कियों के साथ बॉलीवुड, व्यवसाय, खेल, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और सशस्त्र बलों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में सेवाभारती के प्रांत अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने बताया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ ही विश्वगुरु बनाना भी बहुत आवश्यक है। इस प्रयास में समाज का हर वर्ग जुड़े, इसके लिए सेवाभारती प्रयासरत है। रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग और संभ्रांत वर्ग को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समाज का हर वर्ग महिला सशक्तीकरण और किशोरी विकास के उद्देश्य के लिए सम्मिलित होगा।

सेवा भारती की सचिव और कार्यक्रम की संयोजक निधि आहूजा ने बताया कि यह आयोजन हम दिल्ली की सभी सेवा बस्तियों, प्रोफेशनल रनर्स और युवाओं को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के विभिन्न सेवाभावी व्यवसायियों को भी इसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा गया है। सेवाभारती दिल्ली समूचे राज्य की सेवा बस्तियों में 132 किशोरी विकास केंद्र भी शुरू कर चुका है। सेवा भारती का उद्देश्य इन केंद्रों के माध्यम से एक लाख किशोरियों और बेटियों तक सेवाएं पहुंचाने का है। इस कार्यक्रम के लिए क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, पी.टी.ऊषा ने अभी तक इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है।

सेवा भारती के महासचिव सुशील गुप्ता ने बताया कि सेवा भारती महिला सशक्तीकरण, किशोरी विकास के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन के क्षेत्र में दिल्ली में विभिन्न विषयों को समाज के सुधीजनों और सेवाभावी व्यक्तियों के सहयोग से संचालित कर रही है।

लोगों के जीवन के साथ जुआ न खेलें : स्वाति मालीवाल

नई दिल्ली, (हि.स.)। सांसद स्वाति मालीवाल ने आज आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तगड़ा कटाक्ष किया। खास बात यह है कि मालीवाल आआपा की राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने एक्स पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि लोगों के जीवन के साथ जुआ न खेलें। सस्ते और निजी स्वार्थ के लिए पंजाब का उपयोग न करें।

स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा, "सिद्ध मुसेवाला और उन लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, जिन्हें इसकी जरूरत है, लेकिन केजरीवाल उनके सहयोगी विभव कुमार और दिल्ली से आने वाले अन्य लोगों के लिए सैकड़ों बंदूकधारी हैं।" स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल को सरकारी हेलिकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्हें लाने-ले जाने के लिए चार्टर विमान है। उनके करीबियों के लिए चंडीगढ़ में बंगले का भी इंतजाम किया गया है। स्वाति मालीवाल ने पंजाब के प्रमुख विपक्षी नेताओं की सुरक्षा हटाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 'पंजाब के सुपर मुख्यमंत्री' केजरीवाल राजनीति की अपनी सीमाएं होती हैं। जो पंजाब में हो रहा है, वह अनैतिक, अलोकतांत्रिक और खतरनाक है।



नई दिल्ली। सामाजिक संस्था सेवाभारती, दिल्ली द्वारा 13 अप्रैल को यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मैराथन रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड का आयोजन किया जाएगा।

सूडोको बवताल - 7389	***	मध्यम
8 1	2 5	
2		9
5	1	7 4
9 5	4	2
	3 9	6 7
7	8	1 5
	7 2	5
6		7
1 5	6 9	

सूडोको बवताल - 7388 का हल
5 9 4 2 3 6 1 8 7
8 7 3 1 4 5 2 9 6
6 1 2 8 7 9 3 5 4
1 6 7 9 8 2 4 3 5
3 8 5 4 1 7 6 2 9
2 4 9 6 5 3 7 1 8
7 5 6 3 9 1 8 4 2
4 2 1 5 6 8 9 7 3
9 3 8 7 2 4 5 6 1

शब्द पहेली - 8451
1. प्राणेंद्रिय-2
2. लंबी गर्दन वाला पशु-3
4. आपत्त, मुसीबत-2
6. लाचार-3
7. आसरा, मदद-3
8. आश्रय, शरण-3
9. राज कुपूर की पोती-3
10. कर्म, भाग्य-3
11. दासत्व, गुलामी-3
13. आर्टिकल-2
14. इच्छा, लालसा-3
15. दुगंगा, दुगुंगा-2
16. धार-3
17. टेसू के फूल-3
18. राजा का भवन-3
19. चौकसी-2
20. प्रेमी, साजन-3
21. कैनाल, उपनदी-3
23. जीवन सत्व, प्राण-2
24. प्रहार, आक्रमण-3
25. वाट-वाट-2

बाएँ से दाएँ	ऊपर से नीचे
1. अग्निमान-2	19. प्रथम-3
2. मारना, वध करना-2	20. दंड, शिक्षा-2
3. नृत्य, कृष्णलीला-2	21. आंशिक भोग हुआ-2
4. अपसव्य करना-3	22. प्राण, जीवन-2
5. वेस्टइंडीज का कप्तान-2	
6. अज्ञात, अनाम-3	
7. नदी, दरिया-3	
8. जांच, परीक्षण-3	
9. परीक्षा करना-3	
10. जिरा-3	
11. आंचल-3	
12. नाश, विध्वंस-3	
14. अंजन, नेत्रांजन-3	
15. लाइला-3	
16. शक, संदेह-3	
17. तीन घंटे का समय-3	
18. चितन-3	

शब्द पहेली - 8450 का हल
ह क म ग र म ज
द म न म वा ली म
स क ह र ग का म
ली न जा त क ग ज
का र क न ह र क
म म ता वा च न
वा ल क वा न य क
व र त र क म न म

■ Jagrutidaur.com, Bangalore



पटना। चैती छठ पर खरना पूजा के पूर्व गंगा में स्नान करते श्रद्धालु।

बदले की राजनीति करना बंद करे मान सरकार : चुग

दिव्य भारत संवाददाता

चंडीगढ़। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि मान सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, जबकि राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है।

चुग ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर कहा, जब पंजाब में ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं, तब आप सरकार राजनीतिक दुश्मनी निकालने में व्यस्त है। यह शासन नहीं, बल्कि बदले की राजनीति है।

उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनों में 15 से अधिक हमले और ग्रेनेड ब्लास्ट हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पुलिस थानों और पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। अभी दो रात पहले ही पटियाला में एक पुलिस बूथ पर हमला हुआ। इसके बावजूद सरकार की प्रार्थमिकताएं विरोधियों को निशाना बनाना और दिल्ली से आए असफल और जमानती नेताओं का स्वागत करना है यह



शर्मनाक है।

चुग ने सिद्ध मूसेवाला की हत्या का हवाला देते हुए कहा, जब उनकी सुरक्षा हटाई गई थी, तब भी यही अहंकार दिखाया गया था, और उसका अंजाम पूरा पंजाब जानता है। आप के नेता अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते।

उन्होंने आप की दोगली राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली से आए हारे हुए और जमानत पर चल रहे नेता पंजाब में टेक्सपेयर्स

के पैसों से वीवीआईपी सुविधाएं पा रहे हैं, जबकि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है।

आप पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने विपक्ष को हड़ंग माफियाओं से हमददी रखने वाला बताया, तरुण चुग ने पलटवार करते हुए कहा, यह बयान आप नेताओं के अहंकार और तानाशाही रवैये का प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह

के झूठे आरोपों पर कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। अब वही गलती दोहराई जा रही है।

तरुण चुग ने मान सरकार से आग्रह किया कि वह कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करे और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्षियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करे। उन्होंने कहा, अगर शासन नहीं संभाल सकते, तो कम से कम पंजाब की जनता की जान से खिलवाड़ मत करे।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया रामनवमी के दौरान दंगा भड़काने की साजिश का आरोप

कोलकाता, (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर रामनवमी के मौके पर दंगा भड़काने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल के लोग किसी भी हाल में दंगे को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

ममता बनर्जी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बंगाल की संस्कृति शांति और सद्भाव का संदेश देती है। हम रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं, लेकिन 'जुमला पार्टी' को नहीं। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा की कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में बंगाल में ईद का त्योहार पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी तरह आने वाले रामनवमी और अन्नपूर्णा पूजा जैसे त्योहारों को भी शांति से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा, धर्म का

राजनीतिकरण मत करिए। मैं 'जुमला पार्टी' से कहूंगी कि वे बसंती पूजा और अन्नपूर्णा पूजा करें, धर्म का मतलब कर्म होता है। मानवता को अपनाइए, दानवता को नहीं।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी योजनाबद्ध तरीके से रामनवमी के दौरान दंगे भड़काने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, लोगों के बीच फूट डालने और दंगे भड़काने के लिए वे लोग एक नया धर्म लेकर आए हैं। यह धर्म रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, तपोवन, वेद और उपनिषदों का धर्म नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राज्य में रामनवमी के नाम पर सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपये खर्च कर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। गेरुआ खेमे की योजना रामनवमी के मौके पर एक करोड़ लोगों को सड़कों पर लाने की है।

ममता बनर्जी ने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा, महात्मा गांधी ने देश की आजादी

से पहले दंगों को रोकने के लिए अनशन किया था। क्या हम उस इतिहास को भूल जाएंगे उन्होंने दावा किया कि भाजपा सोची-समझी रणनीति के तहत बंगाल की शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी।

मुख्यमंत्री ने अपने हालिया लंदन दौरे के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने विदेश में प्रदर्शन किया और मुझसे पूछा कि क्या मैं हिंदू हूँ। मैं भाजपा को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ।

ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार धर्म के पालन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी धार्मिक कार्यक्रमों को नियमों और प्रशासनिक निदेशों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग किसी भी हालत में सांप्रदायिक हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे और उनकी सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

मदुरै में माकपा का 24वां अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू

मदुरै, (हि.स.)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) का 24वां अखिल भारतीय सम्मेलन बुधवार को मदुरै में शुरू हुआ, जो दक्षिणी जिलों में माकपा का गढ़ है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के पार्टी नेता और प्रतिनिधि कल ही मदुरै पहुंच गए थे। यह सम्मेलन अगले पांच दिनों तक चलेगा। इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनारayi विजयन, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात और बूढ़ा करात सहित अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत ढोल-नगाड़ों के साथ पार्टी का झंडा फहराने से हुई। पार्टी के केंद्रीय नियंत्रण समिति के अध्यक्ष ए.के. पद्मानाभन ने ध्वज ग्रहण किया, जबकि वरिष्ठ नेता बिमान बसु ने इसे फहराया। सम्मेलन में माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य के. बालकृष्णन ने उद्घाटन व्यक्त करते हुए कहा कि तमिलनाडु को तिरुवल्लुवर जैसे विद्वानों, रामानुज, वल्लालार, वैकुंड स्वामी, पंडित अयोध्या दासर और महाकवि सुब्रह्मण्य भारती जैसे प्रगतिशील सामाजिक सुधारों के अप्रदूतों पर गर्व है।



नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरगन ने चिली की संस्कृति, कला और विरासत की मंत्री कारोलिना अरेडोंडो से मुलाकात की।

गुजरात में भाजपा विधायक के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर से बनाए जा रहे थे आधार व पैन कार्ड

सूरत, (हि.स.)। गुजरात के सूरत के वराछा रोड विधानसभा सीट से विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानाणी (किशोर कानाणी) के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने के रैकेट को पुलिस ने पकड़ा है। इस सिलसिले में एमबीए के छात्र को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी छात्र उड़ीसा से फर्जी मुहर बनवाकर लाया था, जिसका उपयोग पिछले तीन महीने से कर रहा था। मामले में पुलिस ने मुहर बनाने वाले एक अन्य आरोपी को वांछित घोषित किया है।

कापोद्रा पुलिस के अनुसार एक अप्रैल की शाम गश्त के समय सर्विलांस स्टाफ को सूचना मिली कि दीपक पटनायक नामक 26 वर्षीय युवक फर्जी मुहर का उपयोग

कर लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम-पता बदलता है। पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर कापोद्रा सौराष्ट्र सर्किल से दीपक पटनायक को पकड़ा। इसके पास से विधायक के नाम की मोहर, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, प्रिंटर, कम्प्यूटर, आधार कार्ड बनाने के लिए भरे हुए व खाली फार्म समेत अन्य सामान जब्त किए गए। आरोपी दीपक ने पूछताछ में बताया कि उसने ओडिशा के संबलपुर से एक अज्ञात व्यक्ति के पास से वराछा रोड क्षेत्र के विधायक कुमार कानाणी के नाम की नकली मुहर बनवाई थी। इसके बाद उसने सूरत के कापोद्रा सौराष्ट्र सर्किल के समीप क्षमा सोसायटी के गेट नंबर-चार के सामने किराए पर ऑफिस लिया था। पिछले तीन महीने से आधारकार्ड और पैन कार्ड में नाम-

पता सुधारने का काम कर रहा था। ग्राहकों से वह प्रत्येक फॉर्म के लिए 200 रुपये फीस लेता था।

पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार ने बताया कि एक टीम बनाकर पांच घंटे में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आरोपी इंदिरागांधी यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। इसके पास से 20 से अधिक भरे और साइन-मुहर मारे फॉर्म कब्जे में लिए गए। विधायक कुमार कानाणी के आधारकार्ड का जेरोक्स भी आरोपी के पास से बरामद हुआ है। मामले में विधायक कुमार कानाणी ने कहा कि किसी भी सरकारी या जन-प्रतिनिधि का फर्जी डॉक्यूमेंट बना कर इसका दुरुपयोग करना बहुत ही गंभीर मामला है। हस्ताक्षर और मुहर का कड़े जगहों पर उपयोग होता है।

बुधवार को पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा समीक्षा समिति की प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी प्रमुख व्यक्ति की सुरक्षा की समय-समय पर संभावित खतरे के मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा की जाती है। इस आधार पर सुरक्षा कवच को बढ़ाया या घटाया जाता है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बिक्रम मजीठिया के पास अभी भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है, जिसमें एस्कॉर्ट वाहन और पर्याप्त संख्या में बंदूकधारी शामिल हैं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी

अकाली दल नेता मजीठिया की सुरक्षा वापस नहीं ली गई, सिर्फ घटाई : पंजाब पुलिस

चंडीगढ़, (हि.स.)। पंजाब पुलिस ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा पूरी तरह से वापस लेने संबंधी रिपोर्टों को सिर से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि खतरे के पुनर्मूल्यांकन के मद्देनजर उनके सुरक्षा कवच को सिर्फ घटाया गया है, वापस नहीं लिया गया।

बुधवार को पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा समीक्षा समिति की प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी प्रमुख व्यक्ति की सुरक्षा की समय-समय पर संभावित खतरे के मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा की जाती है। इस आधार पर सुरक्षा कवच को बढ़ाया या घटाया जाता है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बिक्रम मजीठिया के पास अभी भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है, जिसमें एस्कॉर्ट वाहन और पर्याप्त संख्या में बंदूकधारी शामिल हैं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी

सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

इस बीच बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पत्रकारों से बातचीत में दावा करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल की समूची लीडरशिप तथा कांग्रेस के नेताओं ने उनका समर्थन किया है। मजीठिया ने कहा कि जनवरी माह के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने बम धमाकों की घटनाओं के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई थी। यही नहीं पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने के लिए कहा था। अब सरकार ने राजनीतिक मंशा के चलते उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। मजीठिया ने कहा कि पंजाब पुलिस महानिदेशक उन्हें लिखित में दें कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। वह सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटाने के लिए तैयार हैं। मजीठिया ने हमले व एनकाउंटर की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साथ सिद्ध मूसेवाला जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

हैदराबाद विवि की 400 एकड़ भूमि नीलामी के विरोध में एबीवीपी ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली, (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय सचिव श्रवण बी राज और शिवांगी खारवाल ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान से भेंट कर हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ भूमि के अतिक्रमण और नीलामी के गंभीर मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से इस भूमि को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय को उसका अधिकार वापस दिलाने की मांग की है। इस संदर्भ में अभावित ने तेलंगाना सरकार की मममानी और छात्रों की आवाज को दबाने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। परिषद ने स्पष्ट किया कि शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित इस भूमि का निजी कंपनियों को सौंपा जाना न केवल अनुचित और निंदनीय है बल्कि इससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन को भी गहरी क्षति पहुंचेगी। यह भूमि न केवल शैक्षिक महत्व रखती है, बल्कि अपने समृद्ध जैवविविधता के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय धरोहर भी है। यहां अनेक दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है, जिनके

अस्तित्व पर संकट मंडराएगा। इस भूमि का विनाश जैविक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिससे जलवायु संतुलन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हैदराबाद विश्वविद्यालय की यह भूमि केवल एक भूखंड नहीं बल्कि एक शैक्षणिक और पारिस्थितिक धरोहर है, जिसे किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होने दिया जाए। जब अभावित कार्यकर्ताओं और छात्र समुदाय ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो तेलंगाना पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना जबरन परिसर में घुसकर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। यह न केवल छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है बल्कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर भी सीधा प्रहार है। अभावित ने मांग की कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर इस 400 एकड़ भूमि को तुरंत विश्वविद्यालय को लौटाए और पूरे 2320 एकड़ भूमि का आधिकारिक हस्तांतरण सुनिश्चित करे, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की संभावना समाप्त हो सके।



गुजरात में भाजपा विधायक के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर से बनाए जा रहे थे आधार व पैन कार्ड।

राज्य सरकार नक्सलियों से वार्ता के लिए तैयार : उपमुख्यमंत्री

रायपुर, (हि.स.)। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के शांति वार्ता के प्रस्ताव में नक्सलियों के युद्धविराम जैसे शब्द के प्रयोग पर राज्य के उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार का रुख स्पष्ट किया। नक्सलियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय के शांति वार्ता प्रस्ताव संबंधी पत्र पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है तो फिर युद्धविराम कैसा? राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है। नक्सलियों को हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करना होगा, तभी कोई सार्थक समाधान संभव है। वार्ता के लिए एक उचित माध्यम तय किया जाना चाहिए, ताकि बातचीत से कोई ठोस समाधान निकाला जा सके।

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को मंत्रालय में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है। बशर्ते कि इसके लिए कोई शर्त न हो। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार का रुख साफ है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा और खूनखराबे पर कोई समझौता नहीं होगा। नक्सलियों को

हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करना होगा, तभी कोई सार्थक समाधान संभव है। यदि नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें अपने प्रतिनिधि और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के पास नक्सलियों के लिए बेहतर पुनर्वास नीति है। अगर वे आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका दिया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वार्ता का स्वरूप आईएसआईएस जैसी किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकता। यदि कोई चर्चा करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। अगर वे संविधान को नकारते हैं और समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं, तो वार्ता का कोई औचित्य नहीं रहता। शर्मा ने कहा कि यदि नक्सली वार्ता को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें अपनी ओर से वार्ता के लिए समिति बनानी चाहिए। अब यदि वे बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आगे आना होगा। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक की सबसे बेहतर पुनर्वास

नीति लागू की है। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें इस नीति के तहत सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सरकार चाहती है कि जो लोग भटके हुए हैं, वे समाज में वापस आएँ एक व्यवस्थित जीवन जीयें। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बीते एक से डेढ़ वर्ष में 40 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया, जहां पहले तक नक्सली कानून थोपने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी गांवों में तिरंगा लहराना और भारतीय संविधान का पालन करना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि नक्सलियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने तेलगु भाषा में एक पत्रा जारी कर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकने पर शांति वार्ता के लिए का प्रस्ताव दिया है। प्रवक्ता अभय ने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (गुडचिरोली), ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ऑपरेशन के नाम पर हत्याओं को रोकें, नए सशस्त्र बलों के कैप की स्थापना को रोकें। अगर केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं, तो हम तत्काल युद्धविराम की घोषणा कर देंगे।

सम्पादकीय

हरिभाऊ वाकणकर भीमबैठका और
वैदिककालीन मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे थे

डॉक्टर हरिभाऊ वाकणकर की गणना संसार के प्रमुख पुरातत्वविदों में होती है। उन्होंने भारत के विभिन्न वनक्षेत्र के पुरातन जीवन और भोपाल के आसपास लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे। भीमबैठका उन्हीं की खोज है। उनके शोध के बाद विश्व भर के पुरातत्वविद् भारत आये और डाक्टर वाकणकर से मार्गदर्शन लिया। उनका पूरा नाम श्रीविष्णु श्रीधर वाकणकर था लेकिन वे हरिभाऊ वाकणकर के नाम से प्रसिद्ध थे।

उनका जन्म 4 मई 1919 को मध्यप्रदेश के नीमच नगर में हुआ। पिता श्रीधरजी वाकणकर वैदिक विद्वान थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। बड़े भाई लक्ष्मण वाकणकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियर थे। उन्हें सिरैमिक कला में विशेषज्ञता प्राप्त थी। लिपियों के विकास विशेषकर देवनागरी के डिजिटलीकरण में विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति थी। हरिभाऊ जी की प्रारंभिक शिक्षा नीमच में ही हुई और उच्च शिक्षा केलिये बनारस गये। पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके भीतर भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट स्वाभिमान जागृत किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघ से जुड़ने के लिये प्रेरित किया। वे बालवय में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े गये थे। हरिभाऊ जी बहुत अध्ययन एवं कल्पनाशील थे, स्मरण शक्ति और स्वत्व बोध विलक्षण था। छात्र जीवन में अपनी कक्षा के साथियों और अन्य मित्रों से परस्पर चर्चा में तर्क सहित वे उन धारणाओं का खंडन करते थे जो विदेशी लेखकों ने भारतीय वाङ्मय की गरिमा कम करने के लिये स्थापित की थी। शिक्षा पूरी कर उन्होंने इसी दिशा में कदम बढ़ाये। उन्होंने भारतीय पुरातन साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और पुराणों कथाओं से संबंधित विवरणों के सजीव प्रमाण खोजे। अनेक उन तथ्यों को प्रमाणित किया जिन्हें मिथक कहकर नकारा जाता रहा था। इसमें वेद वर्णित सरस्वती नदी का अस्तित्व भी है।

वाकणकर जी ने सरस्वती नदी की खोज के लिये विश्व इतिहास के इस तथ्य को आधार बनाया कि संस्कृतियों के विकास और इतिहास के प्रमाणीकरण में नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वाकणकर जी ने वैदिक साहित्य में वर्णित सरस्वती नदी की खोज आरंभ की। उन्होंने उपग्रह छवि से प्रमाणित किया कि सरस्वती नदी का प्रवाह हिमालय प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है। आगे चलकर इस मार्ग के लिये एक परियोजना का गठन हुआ जिसके सलाहकार मंडल के संयोजक वाकणकर जी बनाये गये। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को भी सरस्वती नदी से जुड़े होने के प्रमाण दिये। पुरातात्विक खोज के लिये उन्होंने उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। गंगा और नर्मदा के किनारे, विन्ध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षणियों के मैदानों में लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता के चिन्ह खोजे। पर उन्हें मालवा से बहुत लगाव था। इसलिये उन्होंने नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, कायथा, शाजापुर के साथ भोपाल, रायसेन, विदिशा आदि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया और वनक्षेत्र में पदयात्राएँ कीं। उनके जीवनवृत्त के अध्ययन से लगता है कि प्रकृति से उन्हें कोई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त थी। वे पुरातात्विक और खंडित प्रतिमाओं को इतने ध्यान से देखते थे कि लगातार उनसे बातें कर रहे हो। कई बार तो बैठे-बैठे उठकर किसी विशिष्ट स्थान की ओर चल देते थे अथवा चलती ट्रेन में अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर जंगल में उतर जाते थे और उन्हें वहाँ कुछ न कुछ पुरातात्विक खजाना मिल ही जाता था।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग चालीस किलोमीटर दूर भीमबैठका के प्राचीन शिलालिखितों की खोज वाकणकरजी ने की थी। भीमबैठका और भोजपुर के आसपास के कुछ चित्र तो लगभग पौने दो लाख वर्ष पुराने प्रमाणित हुये। इन सभी चित्रों का कार्बन-डेटिंग पद्धति से परीक्षण किया गया। इसका सत्यापन अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने किया। इसी शोध के चलते उन्हें 1975 में पद्मश्री अलंकरण मिला।

वाकणकर जी उज्जैन के सिंधिया ओरियंटल इंस्टीट्यूट से जुड़े थे और भारतीय कला मंदिर उनकी साधना स्थली था। वे न केवल पुरातत्वविद् थे अपितु अच्छे चित्रकार भी थे। उन्हें जितनी विशिष्टता पुरातात्विक अनुसंधान में प्राप्त थी वे उतने ही श्रेष्ठ चित्रकार थे। उनका पूरा जीवन ऋषि परंपरापुरुष था। उन्होंने अपने शिष्यों की एक विशाल मंडली तैयार की। उनमें श्याम सुंदर सक्सेना, गोमति संकुशल, सचिदा नामदेव, मुजफ्फर कुरैशी, राहम गुट्टीवाल्ला आदि प्रमुख रहे। अपने शिष्यों की टोली के साथ उन्होंने चंबल और नर्मदा के बीहड़ों की खोज की और इंग्लैंड तक यात्रा की। उनका शिष्य मंडल मानों परिवार था, उनके व्यक्तित्व का अंग था। वे सुनते अधिक थे बोलते कम थे। जो बोलते मानों ब्रह्म वाक्य होता। उन्होंने जीवन में कभी विश्राम नहीं किया। उन्होंने निरंतर यात्राएँ कीं, भारत के सभी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थानों के साथ विश्व के अनेक स्थानों की यात्रा इसमें शामिल है। वे कभी भी एक झोला कंधे पर टाँग कर निकल पड़ते थे। जिस प्रकार उनके जीवन का आरंभ भारतीय परंपरा, संस्कृति और श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने के अभियान के साथ हुआ था, जीवन का समापन भी कर्मपथ पर हुआ। उन्होंने 4 मई 1988 को सिंगापुर में जीवन की अंतिम श्वास ली।

यह उनके व्यक्तित्व और कार्य क्षमता और ऊर्जा की विलक्षण विशेषता थी कि पुरातात्विक अन्वेषण में अपने अतुलीय और अथक कार्य के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्पों में भी उनकी सक्रियता निरन्तर रही। वे 1981 में स्थापित संस्कार भारती के संस्थापक महामंत्री रहे। वनक्षेत्र में अपने शोध कार्य के साथ उन्होंने संघ की योजनानुसार सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान कार्य भी किये।

पुरातात्विक अनुसंधान और सामाजिक कार्यों के साथ वाकणकरजी ने सिक्कों और शिलालेखों का संग्रह भी किया। उन्होंने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर अब तक के लगभग 5500 सिक्कों और संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी आदि भाषाओं के लगभग 250 शिलालेखों का संग्रह किया। उनके योगदान की स्मृति को सजीव रखने के लिये संस्कार भारती ने 4 मई 2019 से 3 मई 2020 के बीच उनकी जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन किया था। उनका शरीर भले आज संसार में नहीं है पर उनके अनुसंधान सजीव हैं। वे पुरातात्विक अनुसंधान के मील के पत्थर थे। उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी अनुसंधानकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

आरएनआई नं. DELHIN/2009/28518 स्वा.मि., सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक रमाकांत पाण्डेय द्वारा दिव्य भारत प्रकाशन के लिए न-93 डी नारायण नगर दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इन्फोटेक लि., प्रेस, सी-9 सेक्टर 3 नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : रमाकांत पाण्डेय, कार्यकारी सम्पादक : आलोक पाण्डेय, फोन : 7701825882, 7905152597, पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी।

E-mail : newdibyabharat@gmail.com

यमुना की सफाई और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बड़ी चुनौती

मनोज कुमार मिश्र

27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को बतौर वित्तमंत्री एक लाख करोड़ का बजट पेश करके अपनी सरकार के कामकाज की दिशा तय की। दिल्ली के लिए यह ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। बजट में उन सभी कामों के लिए आवंटन किया गया है, जिनके वायदे भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे। कुछ पर तो काम भी शुरू हो गया है और कुछ पर आने वाले दिनों में काम शुरू होने के संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट से करीब 31.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है और उनका दावा है कि इस वित्तीय साल में राजस्व भी 58,750 करोड़ रुपये के मुकाबले 68,000 करोड़ रुपये मिलने वाला है। वैसे तो हर काम में पैसे के साथ-साथ पूरी तैयारी और चौकसी जरूरी है लेकिन यमुना की सफाई के साथ-साथ पानी का संकट दूर करने और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। ये सभी काम केवल पैसे से न होंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान अन्य मुद्दों से ज्यादा ये दोनों मुद्दे प्रभावी रहे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ यमुना की आरती में शामिल हुईं और यमुना को साफ करने का संकल्प दोहराया। यमुना का पानी मानक के हिसाब से तो यमुनोत्री के आगे कुछ ही दूर तक साफ है लेकिन दिल्ली में पल्ला बांध (वजीराबाद) से ओखला यानी 22 किलोमीटर तो गंदे नाले से भी बदतर हाल में है। इसको साफ करने के नाम पर वर्षों से करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस सरकार ने बजट में यमुना की सफाई के लिए नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह वर्षों से प्रयास किया जा रहा है कि यमुना में गंदा पानी जाने से रोका जाए। यमुना को साफ कर उसे अहमदाबाद के सावरमती नदी की तरह विकसित की जाए। यमुना के किनारे कोयले बिजली बनाने वाले संयंत्र सालों पहले बंद कर दिए गए। औद्योगिक कचरे या सीवर के गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्रों के माध्यम से साफ करके ही पानी यमुना में जाने दिया जाए। यमुना को प्रदूषित करने में अव्वल माने जाने वाले नजफगढ़ नाले में इंटरसेप्टर लगाया गया। इस बजट में भी नए इंटरसेप्टर का प्रावधान किया गया है। 1994 में जब यमुना के पानी में दिल्ली को तब के मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना ने हिस्सा दिलाया था, तब

दिल्ली का हरियाणा के साथ एक और समझौता हुआ था कि हरियाणा जितना पानी का पानी पल्ला बांध पर दिल्ली को देगा, दिल्ली उसे उतना ही पानी ओखला बांध पर सिंचाई के लिए देगी। अभी यमुना का पानी साफ होने को ही दिल्लीवासी सपना मान रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली पानी के मामले काफी आत्मनिर्भर हो जाएगी और यमुना साफ होकर दर्शनीय बन जाएगी।

यमुना सफाई जितना ही कठिन काम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त या यहां का प्रदूषण स्तर कम करना है। दिल्ली सरकार के बजट में इसको भी प्राथमिकता दी गई है। अलग-अलग तरीके से प्रदूषण नियंत्रित करने की बात कही गई है लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी तरह के प्रदूषण (वायु, जल और हवा इत्यादि) के साथ-साथ कचरा और अपाद प्रबंधन के लिए एक ही जगह निगरानी व्यवस्था के लिए साझा केन्द्र (इंटिग्रेटेड कमान एंड कंट्रोल सेंटर) बनाने का प्रावधान किया गया है। कहने के लिए 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली है लेकिन एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के शहर दिल्ली से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उन सभी को साथ लिए बिना कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों, दिल्ली नगर निगम और दूसरी सरकारी एजेंसियों को साथ लेकर जनता की सक्रिय भागीदारी से इसका समाधान निकाला जा सकता है।

यह साबित हो चुका है कि केवल आधे कारों को हर रोज सड़क पर आने से रोकने से वायु प्रदूषण में ज्यादा कमी नहीं आने वाली है। दूसरे, सरकारी कुव्यवस्था झेल रहे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस हालत में भी नहीं है कि दिल्ली सरकार इस तरह के प्रयोग बार-बार कर पाए। गिनती के बचे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और सरकार के अधीन चलने वाली बसों की तादाद तुरंत बढ़ानी होगी। इस बजट में सार्वजनिक परिवहन पर 12,952 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बिजली से चलने वाली पांच हजार बसें तुरंत खरीदने का वायदा किया है।

दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के

भीतर आना कम हुआ है। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली के लिए 50 हजार करोड़ की परियोजना बनाई थी, इसमें ज्यादातर पूरे भी हो गए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) समेत अनेक अदालतों ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बार-बार कड़े आदेश दिए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाना भी माना जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान खेत में फसलों के अवशेष जलाते हैं, जिसका धुंआ दिल्ली पर छा जाता है। अदालतों आदेश के बाद सरकारों ने पराली न जलाने और पराली के दूसरे बेहतर उपयोग के प्रयास शुरू किए हैं। इसी तरह एनजीटी ने पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी और डीजल से चलने वाली 10 साल पुरानी कारों पर पाबंदी लगा दी है। बावजूद इसके प्रदूषण कम होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में पहले भी सारे व्यवसायिक वाहनों को अदालतों आदेश से सीएनजी पर चलाया जा रहा है।

हालात एक दिन में खराब नहीं हुए हैं। कुप्रबंधन एवं सरकारी लापरवाही ने दिल्ली के हालात बदतर बना दिए और सुधार के आसार दिख नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 1998 को आदेश दिया कि दिल्ली में चलने वाली सभी बसों को धीरे-धीरे सीएनजी पर लाया जाए। इसकी तारीख 31 मार्च 2001 तय की गई। सरकारें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालती रही तो अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सख्त आदेश दिए। उसके बाद सीएनजी पर बसों और व्यवसायिक वाहनों को लाने की प्रक्रिया तेज हुई। कायदे में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में मिले पैसों से दिल्ली की सड़कों पर बसें दिखने लगीं। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में 15 हजार बसें चलाने का हलफनामा दे रखा है लेकिन अब तो 2010 की बसें भी सड़कों से हटने लगीं और बसों की संख्या गिनती की रह गई है। डीटीसी के अधीन चलने वाली निजी बसें ही सड़कों पर दिख रही हैं। दिल्ली मेट्रो अपनी गति से चल रही है। काफी लोग लोकल रेल से भी यात्रा करते थे, उसे भी अभी ठीक से शुरू नहीं किया गया है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमी के चलते जिसके लिए संभव है, वह अपने वाहन से यात्रा कर रहा है। ऐसे में सड़कों पर से वाहनों की भीड़ कम कैसे हो सकती है?

दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की तादाद एक करोड़ से ज्यादा है। लाखों वाहन एनसीआर के दूसरे राज्यों में पंजीकृत हैं जो हर रोज दिल्ली में चलते हैं। इसलिए कोई भी योजना पूरे एनसीआर के लिए बनाने के बाद ही प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। दिल्ली का न अपना मौसम है और न ही दिल्ली वालों की जरूरत पूरा करने के लिए बिजली और पानी। दिल्ली की किसी भी समस्या का समाधान करना अकेले दिल्ली के बूते नहीं है।

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बेहतर हो ताकि सड़कों से निजी वाहनों की संख्या कम की जा सके। सड़कों को जाम से मुक्त करने के लिए ठोस प्रयास हो। दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों से प्रदूषण कम करने के मानकों पर अमल करवाया जाए। प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी उद्योग को दिल्ली में नहीं चलने दिया जाए। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण रोकने के मानकों पर कड़ाई से अमल हो। पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाए आम जन के जीवन बचाने का मुद्दा बनाया जाए।

इसी तरह आम भागीदारी और सरकारी तंत्र के प्रयास से यह सुनिश्चित करना होगा कि यमुना में एक बूंद भी गंदा पानी न जाए और उसमें किसी तरह का कूड़ा-कचरा डालने पर कठोर दंड दिया जाए। मूल समस्या दिल्ली की अनधिकृत कालोनी और अवैध निर्माण है, जिनमें से ज्यादातर में सीवर प्रणाली है भी नहीं जहां है भी वह कारगर नहीं है। वहां की गंदगी माल रहा है सीवर की गंदगी और गंदा पानी पाइप के रास्ते जल शोधन यंत्रों के बजाए सड़कों और नालों से सीधे यमुना में जा रहा है। इसे कब और कैसे ठीक किया जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। प्रदूषण नियंत्र की तरह ही यमुना भी केवल पैसे के दम पर साफ नहीं हो सकती। सरकार की ताकत, मनसा और जन भागीदारी के बिना न तो दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो पाएगी और न ही यमुना नदी साफ।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकारी संपादक हैं।)

कृषि क्षेत्र में करवट बदलता भारत

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है। इस प्रकार, भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की हैं और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही, भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा।

भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। परंतु, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु, आज इस समस्या को बहुत बड़ी हद तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के

माध्यम से किसान को आसान नियमों के अंतर्गत बैंकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा का लाभ आज देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इससे किसानों की कृषि सम्बंधी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के सफलता मिली है।

भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम कर रही है एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो सके।

देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है और देश में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। जिससे यह किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इन तरह की समस्याओं के हल हेतु अब केन्द्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है, इससे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का

निर्माण) में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है एवं साथ ही परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ की दर पर बेचने में सफल हो रहे हैं अथवा इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है एवं कृषि क्षेत्र को बबादी को रोकने में सफलता मिल रही है।

आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े। इस संदर्भ में मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है इससे किसान कृषि बाजार को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान सीधे ही उपभोक्ता को उचित दामों पर अपनी फसल को बेच सके। साथ ही, कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अग्नि आदि जैसी प्रकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुई फसल के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं।

देश में खेती किसानों का काम पूरे वर्ष भर तो रहता नहीं है अतः किसानों के लिए

अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से डेयरी, पशुपालन, मधु मक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय की सुविधा मिल सके।

विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के प्रारम्भिक चरण में कृषि क्षेत्र का ही सहारा लिया है। औद्योगिक क्रांति तो बहुत बाद में आती है इसके पूर्व कृषि क्षेत्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना होता है। भारत में भी आज कृषि क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि करोड़ों नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी निर्मित करता है। साथ ही, औद्योगिक इकाईयों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र की महत्ता आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार बनी रहेगी क्योंकि इस क्षेत्र से पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए भोजन, उद्योग के लिए कच्चा माल एवं रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र से ही निकलते रहेंगे। हां, कृषि क्षेत्र में आज हो रही प्रौद्योगिकी में प्रगति के चलते किसानों को कम भूमि पर, मशीनों का उपयोग करते हुए, कम पानी की आवश्यकता के साथ प्रकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुई फसल के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं।

देश में खेती किसानों का काम पूरे वर्ष भर तो रहता नहीं है अतः किसानों के लिए

केला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू जैसे कई ताजे फलों एवं चना, भिंडी जैसी सब्जियों, मिर्च, अदरक जैसे प्रमुख मसालों, जूट जैसी रेशदार फसलों, बाजरा एवं अरंडी के बीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों एवं दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। दुनिया के प्रमुख खाद्य पदार्थों यथा गेहूं एवं चावल का भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत वर्तमान में कई सूखे मेवे, कृषि आधारित कपड़े, कच्चे मांस, जड़ और कांड फसलों, दालों, मछली पालन, अंडे, नारियल, गन्ना एवं कई सब्जियों का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत 80 प्रतिशत से अधिक कृषि उपज फसलों (काफी एवं कपास जैसी नकदी फसलों सहित) के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। साथ ही, भारत सबसे तेज विकास दर के साथ पशुधन एवं घुग्गी मांस के क्षेत्र में दुनिया के पांच सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल हो गया है।

कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है क्योंकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है। अधिकतम उपभोक्ता तो आज भी ग्रामीण इलाकों में ही निवास कर रहे हैं एवं उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की मांग भी ग्रामीण इलाकों से ही निकल रही है। अतः देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा।

पेड़ काटना मानव हत्या के समान

राकेश दुबे

अब यह समझ लेना जरूरी है कि कोई कानून और पेड़ों को हल्के में न ले। देश में लगातार जारी पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि एक पेड़ का कटना इंसान की हत्या से भी बदतर है। कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को नये पौधे लगाने की अनुमति तो दी, लेकिन काटे गए 454 पेड़ों के बदले प्रति पेड़ एक लाख रुपये के हिसाब से लगाया जुमाना कम करने से इनकार कर दिया। ऐसा कोर्ट ने अभियुक्त के गलती स्वीकारने और माफी मांगने के बावजूद किया।

इसके जरिये कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कोई

रियायत नहीं दी जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइया की पीठ ने स्पष्ट संदेश दिया कि संबंधित प्राधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि ताजमहल व अन्य पुरातात्विक इमारतों के संरक्षण के लिये बनाये गए ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में 454 पेड़ कटवा दिए गए थे। दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में सहयोग कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव के इस सुझाव पर सहमति जतायी कि कोई कानून और पेड़ों को हल्के में न ले। वहीं, जुमाना लगाने के बाबत भी कोर्ट ने मानक तय किया कि इसमें किसी तरह रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट



ने इस बात को लेकर भी चिंता जतायी कि जो पेड़ काटे गए हैं, उसकी जगह नये पेड़ लगाने के बावजूद इसकी क्षतिपूर्ति में सौ साल लग जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील संरक्षित ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में अदालत ने पेड़ काटने पर वर्ष 2015 से ही प्रतिबंध लगा रखा था। इसके

बावजूद अदालत की अनुमति के बिना सैकड़ों पेड़ काट डाले गए। जिसके बाद न्यायालय ने केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सीईसी को वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाए। बोते वर्ष 454 पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर प्रति पेड़ के हिसाब से एक लाख रुपये का जुमाना लगाया जाए।

कोर्ट ने अभियुक्त की तरफ से

पेश वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की वह दलील ठुकरा दी कि अभियुक्त ने गलती मानते हुए माफी मांग ली है, तो उसे जुमाना कम करके राहत दी जाए। हालांकि कोर्ट ने पास के किसी स्थान पर पौधरोपण करने की अनुमति जरूर प्रदान कर दी है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान

में निरंतर वृद्धि जारी है, वृक्षों का होना प्राणवायु का जरिया ही है। जो हमें शहरों के कंक्रीट के जंगल से उत्पन्न खतरों से बचाते हैं। खासकर पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों में उनकी दोहरी भूमिका है। ऐसे में नीति-निर्णयताओं को सोचना होगा कि कैसे किसी व्यक्ति को संवेदनशील इलाके में पेड़ काटने की अनुमति दी गई। निरंतर बढ़ते तापमान के दौर में वृक्षों के प्रति संवेदनशीलता शासन-प्रशासन के साथ समाज में भी होनी चाहिए। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन और राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिये लोगों के त्याग व संघर्ष को हमें याद रखना चाहिए। जनता का कड़ा प्रतिरोध भी वृक्षों की रक्षा करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।



अखनूर। अखनूर के विधायक मोहन लाल भगत ने बुधवार को अखनूर में नई प्रताप नहर (एनपीसी) के हेड वर्क्स साइट से पानी जारी किया।

ज़िला विकास आयुक्त ने परियोजनाओं का निरीक्षण किया

दिव्य भारत संवाददाता
पुंछ। जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल ने आज यहां ब्लॉक नंगली साहिब-सैन बाबा में निमाणाधीन सड़क संपर्क व अन्य परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण किया। डीडीसी ने एनएच 144ए पर नए टंगली नाला पुल, पुराने टंगली नाला पुल के जीर्णोद्धार और चंदक से देहलान पीएमजीएसवाई सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया।

जीआरआईएफ के कमांडिंग ऑफिसर आशीष रंजन ने जुड़वा पुलों के निर्माण कार्य की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डीडीसी ने परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए काम की गति तेज करने पर जोर दिया।

उन्होंने ओसी जीआरआईएफ को

विशेष रूप से पुराने टंगली नाला पुल के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, साथ ही निर्माण टीम से एनएच 144ए पर नए टंगली नाला पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया।

इसके अलावा, उपायुक्त ने पीएमजीएसवाई के संबंधित कार्यकारी अभियंताओं को मुख्य चौक से नंगली साहिब तक जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा गड्ढों को भरकर सड़क के रखरखाव का निर्देश दिया।

डीडीसी ने गांव कनकोट में नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण घरों का निरीक्षण किया और लाभार्थी तारिक हुसैन के गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया। उन्होंने सरकारी सहायता का प्रभावी ढंग

से उपयोग करने के लिए लाभार्थियों की सराहना की और योजना के प्रभावशाली जमीनी परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। इससे पहले, डीडीसी ने गांव में पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सीएससी के लिए ऑपरेटर की भर्ती में तेजी लाने और इसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे स्थानीय समुदाय को आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में वृद्धि हो सके।

उपायुक्त के साथ सहायक आयुक्त पंचायत, खंड विकास अधिकारी एनएसएसबी और अन्य संबंधित अधिकारी थे, जिन्होंने स्थानीय शासन और सामुदायिक कल्याण में सुधार के लिए समन्वित प्रयास पर जोर दिया।

शिक्षा एक दुर्लभ अवसर है और यह असीम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है : मनोज सिन्हा

आलोक पाण्डेय/दिव्य भारत
श्रीनगर। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में शारदा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने शारदा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों, प्रबंधन, संकाय और छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने युवाओं से विश्वविद्यालय में अर्जित कौशल को राष्ट्र निर्माण और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अच्छे उपयोग के लिए प्रेरित किया।

उपराज्यपाल ने कहा, शिक्षा एक दुर्लभ अवसर है और यह असीम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा ही एकमात्र संपत्ति है और यह एक छोटे से दीपक की तरह है, जिसमें अपार अंधकार को हराने की शक्ति है। युवाओं को शिक्षा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयाम का पता लगाना चाहिए और इसकी मूल्य प्रणाली को संजोना चाहिए। उपराज्यपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्व छात्र नेटवर्किंग और मेंटरशिप, शैक्षणिक संस्थान की प्रतिष्ठा बनाने और ज्ञान साझा करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



उपराज्यपाल ने कहा, पूर्व छात्र एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं और युवा छात्रों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले दो दशक दुनिया में ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे अच्छा समय होने की उम्मीद है। ज्ञान रक्षक के रूप में आप विकास को बढ़ावा देने और विकसित भारत के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय में अर्जित विशेषज्ञता को आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। समाज और राष्ट्र को वापस देने के लिए, पूर्व छात्रों को नौकरियों या

उद्यमों में मूल्य-आधारित प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता विकसित करते हुए युवा पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकें।

उपराज्यपाल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर में शैक्षिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन पर भी बात की। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षण समुदाय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू करने, नवाचार, कौशल विकास, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला अनुकूल वातावरण विकसित करने और युवाओं को सकारात्मक बदलाव का वाहक बनने के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया।

उपराज्यपाल ने कहा हमें एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और इस दृष्टिकोण को शारदा विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा बढ़ावा दिया

■ उपराज्यपाल ने श्रीनगर में शारदा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित किया
■ एलजी ने युवाओं से विश्वविद्यालय में अर्जित कौशल का राष्ट्र निर्माण और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग करने का आह्वान किया
■ युवाओं को शिक्षा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयाम का पता लगाना चाहिए और इसके मूल्य प्रणाली को संजोना चाहिए

जाना चाहिए। हमें निडर और जिज्ञासु दिमागों की जरूरत है जो भारत के लाभ के लिए नवाचार कर सकें और उसका लाभ उठा सकें।

उत्तरी कश्मीर में इको-पार्क स्थानीय इको-टूरिज्म हब के रूप में उभरे

दिव्य भारत संवाददाता
बारामूला। उत्तरी कश्मीर में वन विभाग द्वारा शुरू की गई इको-पार्क पहल इस क्षेत्र को इको-टूरिज्म के हब में बदल रही है। स्थानीय पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, ये इको-फ्रेंडली पार्क स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

स्थायी मनोरंजक स्थान प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थापित ये इको-पार्क सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक बन गए हैं। वे स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। परिवार, छात्र और प्रकृति प्रेमी राजपोरा, कंडी, कैलवान और बाग-ए-तहसीन जैसे इको-फ्रेंडली पार्कों में तेजी से आ रहे हैं, खासकर ईद-उल-फ़ितर जैसे त्यौहारों के दौरान।

पहल की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य वन संरक्षक कश्मीर, इरफान रसूल वानी ने कहा, इको-पार्क पहल कश्मीर के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है, साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति जागरूक पर्यटन को बढ़ावा भी देती है। जैसे-जैसे अधिक स्थानीय लोग इन इको-पार्कों को अपना रहे हैं, यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीने की बढ़ती प्रवृत्ति और क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को बढ़ती समझ को रेखांकित करता है। इन पहलों के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हुए, वन संरक्षक उत्तरी कश्मीर ने जोर दिया कि इन इको-पार्क कार्यक्रम का दोहरा प्रभाव है - पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण दोनों को बढ़ावा देना।

उन्होंने कहा कि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा, इको-

पार्कों ने रोजगार के अवसरों और आगंतुकों की सेवा करने वाले छोटे व्यवसायों के विकास के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया है। पर्यावरण जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए, वन विभाग ने ईद पर विशेष शंकुधारी पौधे वितरण स्टॉल लगाए, जिसमें उत्तरी कश्मीर में हितधारकों के बीच लगभग 37,000 पौधे वितरित किए गए। इन पार्कों की सफलता को अकेले ईद के दिन 22,000 लोगों की कुल संख्या ने और भी अधिक रेखांकित किया, जो कश्मीर की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। क्षेत्र में इको-टूरिज्म के जोर पकड़ने के साथ, वन विभाग इन पहलों को बढ़ाना जारी रखता है, जिससे कश्मीर के प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य सुनिश्चित होता है।

ज़िला विकास आयुक्त ने किश्तवाड़ में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता
किश्तवाड़। जिला विकास आयुक्त राजेश कुमार शवन ने आज जिले में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। बैठक का उद्देश्य क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करना, बाधाओं को दूर करना और पहुंच तथा भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीति बनाना था। नोडल अधिकारी एचएडीपी/मुख्य कृषि अधिकारी अमजद हुसैन मलिक ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। उन्होंने शुरू की गई पहलों, हासिल की गई प्रगति और क्रियान्वयन प्रक्रिया में आई चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कार्यक्रम के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने फ़ील्ड अधिकारियों को बेहतर पहुंच के लिए प्रयास तेज करने, किसानों और हितधारकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा में बागवानी, मत्स्य पालन, भेड़ पालन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में भौतिक और वित्तीय प्रगति का आकलन भी शामिल था। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लक्षित स्वीकृत लाभार्थियों को आगामी वित्तीय वर्ष में कवर किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के भीतर शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।



कटुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मढ़ीन के करियर काउंसिलिंग सेल ने आईबीटी के सहयोग से एक विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया।

विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह, आयुक्त जम्मू नगर निगम ने सैनिक कॉलोनी का दौरा किया

जम्मू। विधानसभा सदस्य डॉ. नरेंद्र सिंह और जम्मू नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने आज सैनिक कॉलोनी का दौरा किया और क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख नागरिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सैनिक कॉलोनी प्रबंधन समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान, स्थानीय निवासियों ने आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी व्यवस्था और स्थानीय पार्कों के विकास जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं को रेखांकित किया गया। समुदाय की शिकायतों को स्वीकार करते हुए, डॉ. यादव ने सैनिक कॉलोनी प्रबंधन समिति को आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह ने नागरिक परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय समुदाय से सुचारु और कुशल विकास पहलों को सुविधाजनक

बनाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।

इसके अलावा, डॉ. सिंह ने निवाचित प्रतिनिधियों को सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके संबंधित क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाएं तेजी से और कुशलता से शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक ने सैनिक कॉलोनी में नागरिक मुद्दों को हल करने की दिशा में एक रचनात्मक कदम उठाया, जिससे समुदाय के कल्याण के प्रति स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता को बल मिला।

बाद में, आयुक्त ने विधायक की मौजूदगी में सैनिक कॉलोनी प्रबंधन समिति को 50 स्ट्रीट लाइट्स सौंपीं।

इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटिंग

को बढ़ाना, निवासियों के लिए बेहतर दृश्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर बोलते हुए, विधायक ने नागरिक आवश्यकताओं को संबोधित करने में जेएमसी के प्रयासों की सराहना की और क्षेत्र में आगे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

आयुक्त ने सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में अच्छी तरह से रोशनी वाली सड़कों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह पहल जम्मू भर में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के हमारे व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हम उन परियोजनाओं को लागू करने के लिए समर्पित हैं जो सीधे निवासियों को लाभान्वित करती हैं, आयुक्त ने कहा। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा, उपायुक्त (दक्षिण) लाल चंद, संयुक्त आयुक्त (पश्चिम) फिरदौस अहमद काजी, कार्यकारी अभियंता (पूर्व), कार्य, जेएमसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व पार्षद और स्थानीय लोग उपस्थित थे।



राजौरी। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को राजौरी सेक्टर का दौरा किया।



बेयत में इजरायली हमले के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों के पास से गुजरती हुई एक महिला।

बांग्लादेश में ढाका-चटगांव राजमार्ग पर 12 घंटे में दो हादसे, 10 की मौत, 27 घायल

ढाका, (हि.स.)। बांग्लादेश के ढाका-चटगांव राजमार्ग पर लगभग 12 घंटों के दौरान दो सड़क हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। आज सुबह हुए हादसे में जान गंवाने वाले सात लोगों में से किसी की भी अब तक पहचान नहीं हो पाई है।

द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, आज सुबह करीब सात बजे चटगांव के लोहागरा उप जिला में ढाका-चटगांव राजमार्ग पर एक यात्री बस और एक मिनी बस के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। लोहागरा पुलिस थाने के प्रभारी आरिफुर रहमान ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो सकी

है। यह हादसा चुंटी राजमार्ग खंड के जंगलिया इलाके में हुआ। रिलेक्स परिवहन की बस की कॉक्स बाजार जा रही एक मिनी बस से टक्कर हो गई। मिनी बस के सात यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी शव लोहागरा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र भेज दिए गए हैं।

इसके अलावा इसी राजमार्ग पर मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे कुमिला के चंदिना उप जिला में एक बस के बिजली के खंभे और पेड़ से टकरा जाने से तीन यात्रियों (सभी पुरुष) की मौत हो गई और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायलों को चंदिना उप जिला स्वास्थ्य केंद्र से कमिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अस्वस्थ, कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया

इस्लामाबाद, (हि.स.)। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। मीडिया में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आने के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से संपर्क किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉन अखबार के अनुसार, हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय या पीपीपी की ओर से अपने सह अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुबह मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति जरदारी को नवाबशाह से लाए

जाने के बाद कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उनकी कुछ जांचें की जा रही हैं और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। प्रेस सूचना विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज ने राष्ट्रपति से संपर्क किया और उनका हालचाल पूछा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच, सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के चिकित्सक डॉ. असीम हुसैन को फोन कर जरदारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। अक्टूबर 2024 में विमान से उतरते समय राष्ट्रपति के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। गिरने के बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

डेमोक्रेटिक बुकर 25 घंटे तक सीनेट में लगातार बोलते रहे राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ

वाशिंगटन, (हि.स.)। अमेरिकी सांसद (सीनेटर) कारी बुकर ने मंगलवार को सीनेट के इतिहास में सबसे लंबा भाषण देकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। न्यूजसी से डेमोक्रेटिक सीनेटर बुकर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध जताते हुए 25 घंटे और पांच मिनट लगातार बोलकर 1957 में सीनेटर स्ट्रॉम थरमंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। थरमंड ने सिविल राइट्स एक्ट के खिलाफ 24 घंटे 18 मिनट तक भाषण दिया था। सीबीएस न्यूज की खबर में बुकर के इस ऐतिहासिक भाषण पर विस्तार से चर्चा की गई है। 55 वर्षीय बुकर ने सोमवार शाम सात बजे (स्थानीय समय) सीनेट के मंच पर अपनी बात शुरू की और मंगलवार रात 8:05 बजे तक लगातार बोलते रहे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य "संयुक्त राज्य सीनेट के सामान्य कामकाज को तब तक बाधित करना है, जब तक मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ।" अपने भाषण की शुरूआत में उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं आज रात इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश संकट में है।"

बुकर का यह भाषण तकनीकी रूप से फिलिबस्टर नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि यह किसी खास विधेयक को रोकने के लिए नहीं था। न ही कार्यवाही को रोकने के लिए किसी विशिष्ट उपाय पर बहस के दौरान हुआ। यह ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ था। बुकर ने भाषण में ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकियों की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और लोकतंत्र की मूलभूत नींव को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। कारी ने कहा कि पिछले 71 दिन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकियों को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बुकर ने मेडिकेड और सोशल सिक्योरिटी में कटौती की आशंका, शिक्षा विभाग पर हमला और ट्रंप की विदेश नीति का तीखा विरोध किया। उन्होंने अपने मतदाताओं के पत्र भी पढ़े। इनमें ट्रंप की नीतियों से होने वाली परेशानियों का जिक्र था। बुकर ने सिविल राइट्स आंदोलन के प्रतीक जॉन लुईस का कई बार उल्लेख किया। इस दौरान कई डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने बुकर का समर्थन किया। इनमें चक शूमर प्रमुख हैं। शूमर ने रिकॉर्ड टूटने के बाद

कहा, क्या आपको पता है कि आपने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है? क्या आपको पता है कि यह समूह आप पर कितना गर्व करता है? क्या आपको पता है कि अमेरिका आप पर कितना गर्व करता है? उल्लेखनीय है कि बुकर पहली बार 2013 में सीनेट में पहुंचे थे। बुकर के कार्यालय ने विज्ञप्ति में कहा कि वे इस अवसर के लिए तैयार की गई सामग्री के 1,164 पृष्ठ लेकर गए थे। बुकर के रिकॉर्ड तोड़ने पर सीनेट कक्ष तालियों से गूंज उठा। बुकर ने अपने भाषण में दिवंगत कांग्रेसी और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुईस जैसे नेताओं की विरासत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब यह देश मुसीबत में था, तब लुईस ने साहस के साथ खड़े होकर साथ दिया। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि हमारा देश संकट में है। बुकर ने भाषण पूरा करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने शुक्रवार को खाना बंद कर दिया और भाषण देने से एक दिन पहले पानी पीना बंद कर दिया ताकि बाथरूम ब्रेक के बिना विस्तारित समय के लिए तैयार हो सकें।



म्यांमार में आये भूकंप के बाद एक अस्थायी राहत शिविर में शरण लेते हुए लोग।

ट्रंप और मस्क को बड़ा झटका, विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेट समर्थित जज क्रॉफोर्ड विजयी

वाशिंगटन, (हि.स.)। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज हर जुबान पर जज सुसान क्रॉफोर्ड की जीत की चर्चा है। प्रिट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी डेमोक्रेटिक समर्थित उम्मीदवार जज सुसान क्रॉफोर्ड के विस्कॉन्सिन राज्य के सुप्रीम कोर्ट की दौड़ जीतने की सुखी है। इस दौड़ के लिए हुए चुनाव में वो जीत गई हैं। उन्होंने इसके लिए मतदाताओं का आभार जताया है। मीडिया में इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी अरबपति एलन मस्क के लिए सबसे तगड़ा झटका बताया गया है। सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तीन महीने से भी कम समय में डेन काउंटी में एक उदार सर्किट कोर्ट जज क्रॉफोर्ड ने रूढ़िवादी उम्मीदवार ब्रैड शिमेल को हरा दिया। वो वीकेशा काउंटी के जज हैं। उन्हें चुनाव अभियान के अंतिम चरण में ट्रंप का खुला समर्थन प्राप्त था। क्रॉफोर्ड की जीत को विस्कॉन्सिन और देशभर में डेमोक्रेट के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। मतदाताओं ने राष्ट्रपति के पसंदीदा उम्मीदवार को पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा में हरा दिया। एलन मस्क ने इस जनमत संग्रह में अपनी निजी संपत्ति के

लाखों डॉलर फूंक दिए। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी न्यायिक प्रतियोगिता बन गई। मंगलवार रात मैडिसन की विजय रैली में क्रॉफोर्ड ने समर्थकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विस्कॉन्सिन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर अभूतपूर्व हमले को विफल कर दिया। विस्कॉन्सिन के लोगों ने साबित कर दिया कि अदालतें बिजली के लिए नहीं हैं। क्रॉफोर्ड ने मस्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्रतियोगिता में उनके बड़े खर्च का संदर्भ दिया। क्रॉफोर्ड ने एक निजी वकील के रूप में प्लॉट पैरेटहुड का प्रतिनिधित्व किया है। वह गर्भपात के अधिकारों का समर्थन करती हैं। क्रॉफोर्ड 10 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। यूएसए टुडे की खबर के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रगतिशील अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने क्रॉफोर्ड को बधाई दी। ओबामा ने मंगलवार रात एक्स पर लिखा, "जज क्रॉफोर्ड को उनकी जीत पर बधाई। विस्कॉन्सिन के लोगों को भी ऐसी जज को चुनने के लिए बधाई, जो कानून के शासन में विश्वास रखती हैं। हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। बर्नी सैंडर्स ने भी क्रॉफोर्ड को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जीत ने एलन मस्क को हराया है।

नेपाल-थाईलैंड प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

काठमांडू, (हि.स.)। थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतेराट्टान शिनावार्ता के बीच बुधवार को बैंकाक में हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। बैंकाक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बैठक में शामिल हुई नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देवना ने कहा कि थाईलैंड के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापना के 65 साल के बाद पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा होना अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावार्ता ने एक सरकारी इमारत में प्रधानमंत्री ओली का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक के बाद संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्री डॉ. आरजू ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इसी तरह दोनों देशों के गैर-सरकारी और व्यावसायिक संगठनों के बीच छह अलग-अलग समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक दूसरे देशों को पर्यटन, शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग आदान प्रदान करने पर जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने अपने थाई समकक्ष के साथ आज आयोजित दोपहर के भोजन में भाग लेंगे और आज ही थाईलैंड के राजा महा वाजिरालोंगकोन के साथ शिष्टाचार बैठक करेंगे।

इजराइल की सेना बमबारी करके दक्षिणी गाजा में घुसी, 17 की मौत

गाजा पट्टी, (हि.स.)। इजराइल की सेना (आईडीएफ) रातभर बरसाते हुए आज सुबह दक्षिणी गाजा में प्रवेश कर गई। इस बमबारी में कम से कम 17 लोग मारे गए। हमस के कई महत्वपूर्ण ठिकाने पलक झपकते ही मटियामेट हो गए। सेना के दक्षिणी गाजा में घुसने पर इजराइल के रक्षामंत्री इजराइल काटज ने कहा कि देश की सेना गाजा पर अपने जमीनी हमले का विस्तार कर रही है। अब गाजा पट्टी में व्यापक क्षेत्र पर कब्जा किया जाएगा। साथ ही आतंकवादी समूह हमस के हमदर्द भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार रक्षामंत्री काटज ने आज कहा कि देश की थल और नभ सेना गाजा पर अपने जमीनी हमले का विस्तार कर रही है। जल्द ही गाजा पट्टी के बड़े भू-भाग पर नियंत्रण कर

उसे गाजा पट्टी के तथाकथित बफर जोन में शामिल किया जाएगा। बताया गया है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में इजराइल ने रातभर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आईडीएफ ने क्षेत्र में एक और डिवीजन तैनात किया है। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार, इजराइल की फौज ने राफाह और खान यूनिस में रातभर कहर बरपाया है। आज सुबह इजराइल के सैनिक राफाह में आगे बढ़ते दिखे। आईडीएफ ने सोमवार को पूरे राफाह क्षेत्र और खान यूनिस के बीच की भूमि के एक बड़े क्षेत्र के लिए निकासी की चेतावनी जारी की थी। अब तक इस क्षेत्र में शांति रही है। कैटज ने कहा कि सेना हर हाल में हमस के आतंकवादियों और उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करेगी। इस बीच गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि बुधवार भोर खान

यूनिस और नुसरात शरणार्थी शिविर में हुए इजराइली हवाई हमलों में बच्चों सहित कम से कम 17 लोग मारे गए। हमस नियंत्रित गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इजराइल के सैन्य अभियान पुनः शुरू करने के बाद से इस क्षेत्र में 1,042 लोग मारे गए हैं।

दरअसल, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमस नेताओं के सामने सशर्त गाजा छोड़ने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि हमस अगर बिना खूनखराबे के बंधकों को रिहा कर दे तो उसके लड़ाकों को गाजा को खाली करने से नहीं रोका जाएगा। गाजा पट्टी में छिड़े युद्ध के दौरान मिस्त्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर से संघर्ष विराम कराने और इजराइली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।



वेंकवूर के हेस्टलिंग पार्क में दूसरे विश्व युद्ध के हथियार प्रदर्शित किये गये।

अमेरिका में 'ट्रंप के टैरिफ' की घोषणा से जीडीपी में आएगी गिरावट : मूडीज

वाशिंगटन, (हि.स.)। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुप्रतीक्षित टैरिफ कुछ लोगों की अपेक्षा से पहले ही लागू होने जा रहे हैं। पूर्व की घोषणा के अनुसार दो अप्रैल देररात या अगले दिन की सुबह अमेरिका शुल्क लागू कर देगा। इस टैरिफ से बाजार में डर का माहौल है। सीएनएन की खबर में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। खबर में कहा गया कि टैरिफ कुछ लोगों की अपेक्षा से पहले ही प्रभावी हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन की 'मुक्ति दिवस' व्यापार नीति की घोषणा को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक आक्रामक कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप आज अपनी व्यापार नीति से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगले दिन शाम चार बजे रोज गार्डन में टैरिफ की घोषणा की जाएगी। घोषणा के साथ यह प्रभावी हो जाएगी। उधर, निवेशकों, अर्थशास्त्रियों और प्रमुख कंपनियों के सीईओ को आशंका है कि आयात करों से लाभ की

बजाय नुकसान होगा। ट्रंप ने सोमवार देररात संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने व्यापक नए टैरिफ की योजना पर सहमति बना ली है। बताया जा रहा कि वह 20 प्रतिशत अधिक के टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप के सलाहकारों ने सार्वजनिक रूप से टैरिफ एजेंडे का समर्थन किया है। मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने कहा कि अगर टैरिफ 20 प्रतिशत से अधिक का हुआ तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थिति होगी। मूडीज के अनुसार, इस व्यापार युद्ध में 5.5 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बेरोजगारी दर सात प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और अमेरिकी जीडीपी में 1.7 फीसद की गिरावट आएगी। जांडी ने कहा कि ट्रंप इस तरह के नुकसान से बचने के लिए उपायों की भी घोषणा कर सकते हैं। टैक्स फाउंडेशन में संघीय कर नीति की उपाध्यक्ष एरिक यॉर्क ने कहा कि ट्रंप का यह अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम होगा। संघीय व्यापार डेटा के अनुसार, आयातित वस्तुओं पर लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर का

टैरिफ लगाया जाएगा। टैक्स फाउंडेशन के अनुसार, व्हाइट हाउस में अपने पूर्व के चार वर्षों के दौरान ट्रंप ने लगभग 380 बिलियन डॉलर के आयात पर टैरिफ लगाया था। इस बार यह टैरिफ तब की तुलना में लगभग 10 गुना बढ़ा होगा। पूर्व राष्ट्रपति विलियम मैककिनले ने 1890 के दशक में आयात पर करों को लगभग 50 फीसदी तक बढ़ा दिया था। इस साल जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद से ट्रंप ने चीन पर टैरिफ में 20, कनाडा और मैक्सिको पर 25 और स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ को 25 प्रतिशत तक बढ़ा चुके हैं। ट्रंप ने अब तक मेन स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट की चिंता की परवाह नहीं की है। बी. रिले वेलथ मैनेजमेंट के मुख्य बाजार रणनीतिकार आर्ट होगन ने कहा कि लोगों के लिए महंगाई की उच्च दरों की उम्मीद करना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने मैककिनले के बाद से इस तरह का व्यापार युद्ध नहीं देखा है। मुक्ति दिवस से पहले अमेरिकी शेयरों में तेजी से गिरावट आई है। निवेशक व्यापार नीति से भ्रमित हैं।



हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एशियन कुश्ती चैम्पियनशिप विजेताओं से की मुलाकात, दी शुभकामनाएं।

आरसीबी बनी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली आईपीएल टीम

बेंगलुरु, (हि.स.)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इंस्टाग्राम पर अपनी लोकप्रियता के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। टीम ने 18 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे वह इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी बन गई है। आरसीबी ने अपने अनोखे और आकर्षक कंटेंट के जरिए फैंस से गहरा जुड़ाव बनाया है, जिससे सोशल मीडिया उनके लिए ब्रांड ग्रोथ और कमर्शियल एंगेजमेंट का एक मजबूत जरिया बन गया है। यह जानकारी फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में दी गई।

पिछले साल नवंबर 2023 तक आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और मुंबई इंडियंस (एमआई) से पीछे थी। हालांकि, टीम की प्रभावी सोशल मीडिया रणनीति और फैंस की जबरदस्त निष्ठा ने उसे इस रेस में आगे ला दिया। अब आरसीबी के 18.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि

सीएसके के 17.8 मिलियन और एमआई के 16.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आरसीबी ने 23 मार्च को 17 मिलियन का आंकड़ा छुआ था और महज 10 दिनों में 18 मिलियन तक पहुंच गई।

आरसीबी की सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के पीछे उनकी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ऐतिहासिक जीत भी एक बड़ी वजह रही। टीम ने 17 साल बाद सीएसके को उनके घरेलू मैदान पर हराया, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर टीम को जबरदस्त सपोर्ट मिला और फॉलोअर्स की संख्या में तेजी आई।

आरसीबी के मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) राजेश मेनन ने कहा, हम अपने फैंस के जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हर दिन उनसे जुड़े रहना चाहते हैं और प्रासंगिक व दिलचस्प कंटेंट देना चाहते हैं। हमारी सोशल मीडिया रणनीति की सफलता

का श्रेय हमारी प्रामाणिकता और खिलाड़ियों की व्यक्तिगत कहानियों को उजागर करने को जाता है। सोशल मीडिया हमारे फैंस के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बनाने का माध्यम बन गया है।

आरसीबी इस सीजन में न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मैदान पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम फिलहाल अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। आरसीबी ने अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है। पहले मैच में उन्होंने गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को हराया, वहीं दूसरे मैच में उन्होंने पांच बार की चैंपियन सीएसके को उनके ही घरेलू मैदान पर शिकस्त दी।

आरसीबी का अगला मुकाबला बुधवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैदान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी बढ़त बनाए रखेगी।

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रनों से हराकर जीती सीरीज

हैमिल्टन, (हि.स.)। न्यूजीलैंड ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए 84 रनों की जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। अब कीवी टीम शनिवार को माउंट माउंगानुई में होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे में क्लीन स्वीप करने उतरेगी।

मैच में न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी सफलता तेज गेंदबाज बेन सियर्स को मिली, जिन्होंने अपने तीसरे वनडे में ही पांच विकेट झटककर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया।

सियर्स ने अपने पहले दो वनडे में कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने 59 रन देकर 5 विकेट झटके और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

293 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। विल ओ'रूके ने पहले ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक (1) को आउट कर दिया। इसके बाद बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने। इमाम-उल-हक (0) भी डफी की गेंद पर आउट हुए, जिससे पाकिस्तान 5.3 ओवर में ही 9/3 के स्कोर पर

संघर्ष कर रहा था। इसके बाद भी टीम की हालत नहीं सुधरी। सलमान आगा (9) के रूप में चौथा विकेट गिरा, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान भी 27 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर (13), मोहम्मद वसीम (1) और अकिफ जावेद भी जल्दी आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान की हार लगभग तय हो गई थी।

हालांकि, फहीम अशरफ और नसीम शाह ने 60 रनों की साझेदारी कर कुछ संघर्ष दिखाया। अशरफ ने 80 गेंदों में 73 रन बनाए, जबकि नसीम शाह ने 44 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली। लेकिन उनकी ये पारियां न्यूजीलैंड की जीत को रोकने के लिए काफी नहीं थीं। न्यूजीलैंड के लिए बेन सियर्स ने 5 विकेट (5/59) लिए, जबकि जैकब डफी ने 3/35 का शानदार प्रदर्शन किया। विल ओ'रूके और नाथन स्मिथ को भी एक-एक विकेट मिला, जिससे पाकिस्तान 43.4 ओवर में 208 रन पर ऑलआउट हो गया और न्यूजीलैंड को 84 रनों की बड़ी जीत मिली।

इससे पहले न्यूजीलैंड ने 292/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। राइस मारियू (18) और निक केली (31) ने टीम को तेज

शुरुआत दिलाई। हालांकि, 6.2 ओवर में 54/1 पर पहला विकेट गिरा। टीम ने 15.3 ओवर में 100 रन पूरे किए, लेकिन इसी ओवर में डेरिल मिचेल (18) आउट हो गए। इसके बाद हेनरी निकोल्स (22) और कप्तान माइकल ब्रेसवेल (17) के आउट होने से न्यूजीलैंड 132 रन पर 5 विकेट खोकर मुश्किल में आ गया।

इसके बाद मोहम्मद अब्बास और मिशेल हे ने 77 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। अब्बास 41 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मिशेल हे ने अंत तक बल्लेबाजी की और 78 गेंदों में नाबाद 99 रन बनाए। उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए और शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पाकिस्तान की ओर से सुफियान मुक़ीम (2/33) और मोहम्मद वसीम (2/78) ने सबसे ज्यादा विकेट लिए।

सीरीज पहले ही जीत चुकी न्यूजीलैंड की टीम अब शनिवार को होने वाले तीसरे वनडे में पाकिस्तान को हराकर 3-0 की क्लीन स्वीप पूरी करने के इरादे से उतरेगी। पाकिस्तान के लिए यह आखिरी मौका होगा कि वह इस दौर पर कोई जीत दर्ज कर सके।



न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रनों से हराकर जीती सीरीज, तीसरे वनडे में क्लीन स्वीप का मौका।

दिल्ली

शराब तस्करी के मामले में दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से दो महिलाओं समेत चार शराब तस्करी को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान साहिल, मोनु सिंह उर्फ मन्नु, प्रीति तथा दोला के रूप में हुई है। आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने 30 पेटी शराब बरामद की है। शराब तस्करी में प्रयुक्त एक स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की है।

दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बुधवार को बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर डाबड़ी एक्सप्लॉरेशन के समीप नाला रोड पर ऑटो से बोरियां लेकर उतरी प्रीति राणा को गिरफ्तार किया। उसके पास मौजूद बोरियों की तलाशी ली गई तो उनमें से 14 पेटी शराब बरामद हुई। वहीं, स्पेशल स्टॉफ की टीम को इंद्रा पार्क, सागरपुर में अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना मिली। टीम ने गली नंबर 10 इंद्रा पार्क में छापेमारी कर स्कूटी पर शराब ला रहे मोनु सिंह उर्फ मन्नु को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 2 पेटी शराब बरामद हुई। उसकी निशानदेही पर 6 पेटी शराब बरामद की गई। इसी क्रम में सागरपुर थाना पुलिस ने ईस्ट सागरपुर से साहिल नामक शराब तस्कर को पकड़ा। उसके कब्जे से पांच पेटी शराब जब्त की गई। वहीं दिल्ली कैट इलाके से किरबी प्लेस झुग्गी बस्ती से दोला नामक महिला को 3 पेटी अवैध शराब के साथ पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया।

हंगामा करने पर आतिशी समेत विपक्ष के 12 विधायक सदन से निष्कासित

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आआपा) के 12 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। उन्हें मार्शलों ने जबरन सदन से बाहर निकाला।

आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आआपा विधायकों ने हाथ में कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग वाले प्ले कार्ड लेकर सदन की वेल में नारेबाजी करने लगे। विधानसभा

अध्यक्ष द्वारा बार-बार मना करने के बावजूद आआपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आआपा के 12 विधायकों को मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। इन विधायकों में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, कुलदीप कुमार, संजीव झा, सहाराम पहलवान, प्रेम कुमार चौहान, विशेष रवि, मुकेश अहलावत, अली मोहम्मद इकबाल, जयलाल सिंह, अनिल झा, सुरेंद्र कुमार और सोम दत्त शामिल हैं।

मार्शलों द्वारा हंगामा कर रहे आआपा विधायकों को सदन से बाहर निकाले जाने पर पार्टी के अन्य विधायक भी विरोध स्वरूप

सदन से बाहर चले गए। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को दस मिनट तक स्थगित कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आआपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में बैनर और प्ले कार्ड लेकर कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी ने कहा कि कोर्ट ने दिल्ली दंगों में भड़काऊ भाषण के लिए कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं।

जब दिल्ली दंगों के सभी आरोपित तिहाड़ जेल में हैं तो क्यों दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कपिल मिश्रा

को मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में भूमिका के संबंध में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच करने का आदेश दिया है। एडिशनल चीफ जस्टिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसके पहले कड़कडूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

एनएचआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में जबर्दस्त प्रगति हासिल की

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास की दिशा में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जबर्दस्त प्रगति की है। प्राधिकरण ने इस दौरान निर्धारित 5,150 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 5,614 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में एनएचआई द्वारा पूंजीगत व्यय 2,40,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 2,50,000 करोड़ रुपये (अंतिम) से अधिक के एनएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

अब तक के इस सबसे अधिक पूंजीगत व्यय में सरकारी बजटीय सहायता और एनएचआई के अपने संसाधन दोनों शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 2,07,000 करोड़ रुपये की तुलना में कुल पूंजीगत व्यय में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2022-23 में 1,73,000 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान एनएचआई ने मुद्रीकरण के लिए तीन तरीकों का लाभ उठाया, जिसमें टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इवआईटी) और टोल सिक्योरिटाइजेशन शामिल थे। वित्तीय वर्ष के दौरान एनएचआई ने कुल 28,724 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रही तत्कालीन दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, (हि.स.)। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सदन ने वर्ष 2021 में समाप्त हुए वर्ष के लिए 'दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन' के निष्पादन लेखापरीक्षा पर सीएजी की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दिल्ली की जनता से जुड़े प्रदूषण और विशेष रूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा की गई है।

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है और इसे तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। इसके बावजूद तत्कालीन दिल्ली सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोक लेखा समिति को इस रिपोर्ट की गहन जांच करनी चाहिए और उन व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे। रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार तत्कालीन सरकार की ओर से गंभीर खामियां की गई प्रतीत होती हैं। पीएसी तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और विभागों की एक महीने के भीतर अपने एक्शन टेकन

नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जैसा कि सीएजी रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से परिवहन मोड में बदलाव, प्रवर्तन प्रणाली को मजबूत करना जैसी कुछ ऐसी रणनीतियां थीं, जिनका उपयोग, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जा सकता था। रिपोर्ट में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में विभिन्न कमियों की ओर इशारा किया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सरकार के पास वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए कोई प्रभावी तंत्र या बुनियादी डेटा तक नहीं था। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया और बड़ी संख्या में डीटीसी बसें सड़कों पर नहीं उतरीं। बजट प्रावधान रखने के बावजूद मोनोरेल, लाइट रेल ट्रांजिट या इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसें जैसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वैकल्पिक तरीकों को शुरू करने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्रों में गंभीर अनियमितताएं थीं। प्रदूषण जांच

केंद्रों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में 2018-2019 में, 64 प्रतिशत वाहनों का फिटनेस चेक किया जाना था लेकिन उन्होंने फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया और 90 प्रतिशत से अधिक फिटनेस टेस्ट केवल दृश्य निरीक्षण के आधार पर किए गए, जिससे टेस्टिंग की प्रक्रिया व्यर्थ हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल 2020 में बीएस-कम और बीएस-कx वाहनों का पंजीकरण किया गया। 47.51 लाख अपनी अवधि पूरी करने वाले वाहनों में से, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना था, उनमें से वास्तव में केवल 2.98 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। ऑड-ईवन, टर्कों पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की शुरुआत जैसे उपायों को ठीक तरह लागू नहीं किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा लगता है कि विज्ञापनों और मीडिया में किए गए बेबुनियाद दावों के विपरीत, तत्कालीन सरकार ने दिल्ली के लोगों को वाहनों से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिससे जानलेवा बीमारियों सहित गंभीर कठिनाइयां सामने आ रही हैं।



नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास की दिशा में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जबर्दस्त प्रगति की है।



वाराणसी। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर स्थित माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए विभिन्न संगठनों के साथ श्रद्धालु महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा।

ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए उमड़ श्रद्धालु

■ वर्ष में एक बार खुलता है दरबार, शंखनाद, डमरू वादन और मंत्रोच्चार से पूरा धाम परिक्षेत्र गुंजायमान

वाराणसी, (हि.स.)। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर स्थित माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए विभिन्न संगठनों के साथ श्रद्धालु महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए खुलने वाले माता के दरबार में दर्शन पूजन के लिए मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाओं व हिंदू पक्ष के पैरोकार, अधिवक्ताओं के साथ ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ता भी पहुंचे। दरबार में श्रद्धालु महिलाओं ने विधि विधान से माता का दर्शन कर श्रृंगार सामग्री अर्पित कर उनसे सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। इसके पहले वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में मैदागिन स्थित गोरखनाथ मठ मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए

शोभायात्रा यात्रा निकाली गई। इसमें चारों वादिनी महिलाएं भी शामिल हुईं। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों को बताया कि हम मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनके चरणों में हम कामना करेंगे कि जो न्यायालय में संघर्ष चल रहा है, उसमें विजय प्रदान करें। इसी क्रम में ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के जल्ये ने भी माता रानी की आरती उतारी। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं को सत्यनारायण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार-बी से सुबह 8.30 बजे से प्रवेश दिया गया। दर्शन पूजन में महिला दर्शनार्थियों को वरीयता दी गई, जिससे उनकी लाइन आगे रही।

ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के बैनर तले श्रद्धालुओं का दल कलश में गंगा जल लेकर मंदिर में पहुंचा। 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी उद्घोष, शंखनाद, डमरू वादन और मंत्रोच्चार से पूरा धाम परिक्षेत्र गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने मां श्रृंगार गौरी की प्राचीन प्रतिमा के टूटे पथरों पर सिंदूर और चंदन का लेपन किया। इसके बाद पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ माता की आराधना की। इसी क्रम में चौक चित्रा सिनेमा के पास से भी श्रद्धालुओं की भीड़

गुलशन कपूर के नेतृत्व में दर्शन पूजन के लिए ज्ञानवापी पहुंचा। श्रद्धालु हाथों में पूजन सामग्री, माला फूल, ध्वज लेकर दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने ज्ञानवापी कूप के जल से माता के विग्रह को स्नान कराया। फिर गुलाब, अड़हुल, बेला के फूलों से श्रृंगार कर माता को सिन्दूर अर्पित किया। इसके बाद माता रानी से भव्य मंदिर बनने की गुहार लगाई। माता श्रृंगार गौरी के दर्शन के बाद दल ने ज्ञानवापी कूप के जल से काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। माता अन्नपूर्णा और दुर्गाराज गणेश का

दर्शन कर जल्ये ने ज्ञानवापी परिसर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर दर्शन पूजन यात्रा को विराम दिया और वापस अपने घरों को लौटे। इसके पहले मंगलवार शाम को श्री काशी विश्वनाथ धाम के सभागार में ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद की बैठक हुई। इसमें माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन कार्यक्रम, ज्ञानवापी व्यास जी तहखाना और बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन की रूप रेखा बनी। इस बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र, मंदिर के डिप्टी एसडीएम शंभू शरण, पुलिस उपकुप, ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद से डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्र, अधिवक्ता अनघ शुक्ल, पतंजलि पांडेय आदि की उपस्थिति रही।

बाउण्डी वाल की स्थिति ठीक नहीं होगी तो होगा मुकदमा दर्ज : डीएम

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में हर तरफ कमियां ही कमियां ही देखने को मिली। कमियां ही कमियां देखकर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी का पारा गर्म हो गया और उन्होंने सभी की जमकर कत्तास ली।

जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के द्वारा बाउण्डीवाल का निर्माण कार्य किया जा रहा था। बाउण्डीवाल के निर्माण को देखने के बाद यूपीपीसीएल के एई गणेश प्रसाद को निर्देश दिया कि 15 मई तक बाउण्डी वाल का काम पूरा कर लिया जाये और बाउण्डीवाल बनाने में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। यदि कमेटी के द्वारा जांच रिपोर्ट में बाउण्डी वाल की स्थिति ठीक नहीं होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में दर्शक दीर्घा की जर्जर स्थिति देखने के बाद जिलाधिकारी ने आरईडी एवं पीडब्लूडी

- जिलाधिकारी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया निरीक्षण
- निरीक्षण के दौरान स्टेडियम में मिली खामियां ही खामियां
- स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए गठित समिति प्रत्येक 15 दिवस में स्टेडियम की रिपोर्ट उपलब्ध कराये

के अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिया कि दर्शक दीर्घा का ध्वस्तीकरण किया जाए और पुनः नया स्टीमेट बनाकर आवश्यक कार्यवाही की जाये। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में खिड़कियों की जालियां टूटी मिली जिस पर नयी जाली लगाये जाने और कार्यालय की रंगाई-पुताई का कार्य कराने को कहा गया। बैडमिन्टन हाल की भी हालत ठीक नहीं होने पर यूपीपीसीएल के एई गणेश प्रसाद को निर्देश दिया कि जो भी छत पड़ी हुई है उसे नये सिरे से मरम्मत व रंगाई पुताई एवं प्रकाश की व्यवस्था करायी जाये और जो फर्श की तरह लकड़ी लगी थी उसे

हटाकर नयी लकड़ी लगाया जाये। टेबुल टेनिस और कुश्ती हाल में भी कमियां पाई गई, एई को निर्देश दिया कि टेबुल टेनिस, कुश्ती हाल, बैडमिन्टन हाल और कार्यालय के मरम्मत कार्यों को 15 अप्रैल से शुरू कर दिया जाये और 30 जून तक कार्य को पूरा कर लिया जाये। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम हेतु जो भी समिति गठित की गयी है वह प्रत्येक 15 दिवस में स्टेडियम की रिपोर्ट उपलब्ध कराये। वहीं स्टेडियम के बगल कृषि विभाग की खाली जमीन को देखकर एसडीएम



सदर से कृषि विभाग की जमीन को नजरी नक्शा के साथ प्रपोजल बनाकर प्रस्तुत करने को कहा, जिससे स्टेडियम के विस्तार

के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा सके। स्टेडियम में बने जिम में एसी नहीं लगी थी जिस पर रायफल क्लब से एसी लगाये जाने और आरईडी के अधिशासी अभियन्ता सुजीत राय को निर्देश दिया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में 8 रूम स्टेडियम में 4 बैरक बनाये जाये। बाउण्डी वाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बाउण्डी के किनारे अशोक के वृक्ष लगाये जाये।

इस दौरान क्रीड़ाधिकारी पूनम लता राज उपस्थित रही।

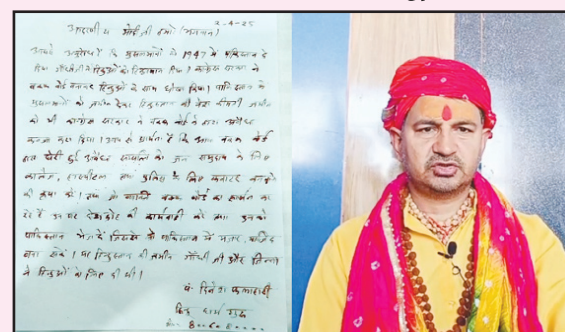
संक्षिप्त समाचार

शराबी कर रहा है बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का रखरखाव

दिव्य भारत संवाददाता

प्रतापगढ़। जीआईसी परिसर में बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को रखवा गया है, इन्हीं कॉपियों के रखरखाव के लिये राजकीय इंटर कॉलेज पूरबागव अंतु में चपरासी पद पर तैनात रामलालन पुत्र दूधनाथ हेला निवासी किठावर बाजार थाना अंतु की ड्यूटी लगाई गई है। यह चपरासी आज शराब के नशे में टल्ली होकर जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस के सामने सड़क के किनारे शराब के नशे में पड़ा हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार जब जिला विद्यालय निरीक्षक अपने ऑफिस से निकले तो देखा कि रामलालन शराब के नशे में गिरा पड़ा हुआ था, तब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना पर मिलने पर भुलियापुर चौकी ईंचार्ज अंकित तिवारी मौके पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद चौकी ईंचार्ज अंकित तिवारी के द्वारा नशे में पड़े रामलालन के मुंह पर पानी मार कर होश में लाया जाता है। सवाल यह उठता है कि ऐसे नशेड़ी बोर्ड की कॉपियों का रखरखाव कर पायेंगे?

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास अध्यक्ष ने लिखा प्रधानमंत्री को खून से पत्र



मथुरा, (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खून से पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि वक्फ की जमीन पर कॉलेज और अस्पताल बना दिए जाए। दिनेश ने लिखा है कि 1947 में हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान दिया गया था और मुसलमानों के लिए जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को हमेशा उगने का काम किया है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाकर हिंदुस्तान की बेशकीमती जमीन मुसलमानों को दे दी। आगे लिखा है कि आप हिंदुओं के गौरव हैं आपसे ही उम्मीद बची है। वक्फ बोर्ड की इस अवैध सम्पत्ति की जांच करा कर इस पूरी सम्पत्ति को कॉलेज, अस्पताल और पुलिस क्वार्टर के लिए दे दी जाए, जिससे जन समुदाय उसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड का समर्थन करता है वह देश विरोधी है।

1.01 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले तीन गिरफ्तार

गाजियाबाद, (हि.स.)। थाना साइबर क्राइम ने बुधवार को रियल 11 गेमिंग मोबाइल एप के पेमेंट गेट-वे को हैक कर 1.01 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले तीन ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपित पिता-पुत्र हैं। इनके कब्जे से चेक बुक, पासबुक, एटीएम व मोबाइल फोन बरामद किये गये। आरोपितों के 25 लाख रुपये फ्रीज करवाये गए। एडीसीपी पीयूष सिंह ने पत्रकारों को बताया कि अमित यादव के साथ उनकी कम्पनी के रियल 11 गेमिंग मोबाइल एप पेमेंट गेट-वे को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। अपराधियों ने यूजर आईडी वाले बनावट पर कुछ पैसे जमा कर गेमिंग एप के पेमेंट गेटवे को हैक कर पैसे जमा किया। इसके बाद जमा किए गए धनराशि से अधिक धनराशि वाले टैट में जमा दिखाकर अपने वालेट से रिफंड के रूप में विभिन्न खातों में कुल 1,01,14,095 रुपये निकालकर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया।

गाजियाबाद में दो जगह पुलिस व बदमाशों के बीच चली गोलियां, दो हत्यारोपित समेत तीन बदमाश गिरफ्तार

गाजियाबाद, (हि.स.)। दिल्ली से ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार की रात में दो अलग-अलग मुठभेड़ में तीन शांतिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी इन बदमाशों पर गोलियां चला दीं। जिसमें दो अपराधियों के पैर में गोली लगी और घायल हो गए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो बदमाशों ने पिछले दिनों कीशम्बी में हत्या करने की घायल का इकबाल किया है। पहली मुठभेड़ साहिबाबाद क्षेत्र में हुई एसीपी साहिबाबाद श्वेता कुमारी यादव ने बुधवार की सुबह बताया कि साहिबाबाद पुलिस फरखनगर रोड पर बटर पाठ मोड़ के पास चैकिंग कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन वे भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया और दोनों को घेर लिया।

आमजन को मिले सुगम यातायात की सुविधा, दूसरे दिन भी चला चाबुक

दिव्य भारत संवाददाता

लखनऊ। नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा मिले और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए प्रदेश में दूसरे दिन बुधवार को भी अवैध ई-रिक्षा व ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार से पूरे प्रदेश में अभियान शुरू किया गया था।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अभियान मंगलवार से प्रारंभ हुआ था। अभियान के दूसरे दिन 1007 ई-रिक्षा सीज और 3093 का चालान हुआ। वहीं मंगलवार को 915 ई-रिक्षा सीज किया गया था, जबकि 3035 का चालान हुआ था। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

- अवैध ई रिक्षा व ऑटो के खिलाफ बुधवार को भी हुई कार्रवाई
- अभियान के दूसरे दिन बुधवार को प्रदेश में 1007 ई-रिक्षा सीज और 3093 का हुआ चालान
- आगरा संभाग में 444, लखनऊ में 377 और कानपुर में 277 ई-रिक्षा पर हुई कार्रवाई

अभियान के नोडल अधिकारी अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया कि बुधवार को आगरा संभाग में 444, लखनऊ संभाग में 377, कानपुर में 277, गाजियाबाद संभाग में 257, झांसी में 216, का चालान हुआ था। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

फेसबुक लाइव के माध्यम से यूपी में नौ लाख से अधिक गन्ना किसान प्रशिक्षित

आलोक पाण्डेय/दिव्य भारत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों के विकास पर खासा फोकस है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गन्ने की खेती के लिए जो प्रोत्साहन और प्रयास किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन और उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है। इसी क्रम में गन्ना शोध संस्थानों के साथ विशेषज्ञ फेसबुक लाइव के माध्यम से गन्ना किसानों को अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

गन्ना विकास परिषद ये प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी-24 से चला रही है। जिसकी पहुंच 15 लाख से अधिक गन्ना किसानों तक हो चुकी है। फेसबुक लाइव से प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ प्रदेश के किसानों के साथ उत्तराखंड और नेपाल के गन्ना किसानों को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन

में गन्ना विकास परिषद प्रदेश के गन्ना किसानों को आधुनिक तकनीकी से परिचित करवाने के लिए जहां एक ओर शोध संस्थानों में प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। फेसबुक लाइव के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी चला रहा है। फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रशिक्षण देने के साथ-साथ गन्ना किसानों की समस्याओं का भी त्वरित हल प्रदान किया जाता है। फेसबुक लाइव के माध्यम से गन्ना किसानों को प्रशिक्षण देने से इसकी पहुंच कम समय में अधिक गन्ना किसानों तक प्रत्यक्ष रूप संभव हो रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और नेपाल के गन्ना किसान भी प्राप्त कर रहे हैं।

उप गन्ना विकास परिषद, फेसबुक लाइव के साथ ही शोध संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक तरीके से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। गन्ना विकास

परिषद मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और सेवरही संस्थानों में निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इन गन्ना कृषि शोध संस्थानों में भी अब तक 19,039 किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही मेरठ, रामपुर, लखीमपुर, बरेली, हरदोई, पीलीभीत के साथ नेपाल में भी प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों के साथ कृषि की आधुनिक तकनीकों से परिचित करवाना है। गन्ना विकास परिषद के प्रवक्ता के मुताबिक गन्ना किसानों को न केवल गन्ना की खेती, बल्कि मूल्य भुगतान, बीज की उपलब्धता जैसी समस्याओं का भी निदान किया जाता है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता में नंबर वन होने के साथ चीनी उत्पादन में भी देश में सबसे आगे है।

भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी सलमान गिरफ्तार

जालौन, (हि.स.)। कोटरा थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी की गई। जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने वाले वर्ग विशेष के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। भगवान राम के खिलाफ की गई टिप्पणी से गुस्साए लोगों द्वारा थाना के बाहर मुख्य सड़क में जाम लगाकर घंटों नारेबाजी की गई।

बता दें कि, कस्बा कोटरा मुगलाना घाट निवासी युवक सलमान मंसूरी ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसकी खबर जैसे ही हिंदू समुदाय को हुई, लोग आक्रोशित हो गए। थोड़ी ही देर में सैकड़ों लोग थाना कोटरा पहुंच गए एवं आरोपित को कड़ी सजा की मांग करने लगे।

नाराज लोग थाना परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी करने लगे। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस संघर्ष

की जानकारी होते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह ने थाना आकर लोगों को समझाया बुझाया एवं आरोपित पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

कोटरा निवासी मनीष व्यास, अंकित गुप्ता, अभिषेक, अमित कुमार सहित एक दर्जन से अधिक लोगों ने कोटरा थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आरोपित ने जानबूझकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उसके खिलाफ कोटरा कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस द्वारा आरोपी सलमान के खिलाफ धारा 299, 353, 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, तब कहीं जाकर घंटों मशकत के बाद लोग अपने घरों को लौटे। कोटरा थाना अध्यक्ष विमलेश कुमार, एस एसआई गोकुल सिंह ने आरोपित सलमान को खदानी नहर से मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सलमान को धारा 299, 353, 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।



जालौन। भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपित सलमान गिरफ्तार।